हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 343 बेमेतरा, रविवार 09 अगस्त 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

नक्सल हिंसा प्रभावित 15 परिवारों को 2.25 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल पर मिली राहत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और छत्तीसगढ़ नक्सलवाद पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में 15 पीड़ित परिवारों के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

यह सहायता उन परिवारों को दी गई है, जिनके परिजनों की नक्सली हिंसा में मृत्यु हो गई थी और विभिन्न कारणों से उन्हें शासकीय सेवा प्रदान करना संभव नहीं था। ऐसे मामलों में नीति के तहत शासकीय सेवा के बदले प्रत्येक मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

स्वीकृत सहायता राशि का लाभ कल्लू ताती, भदरू सोढ़ी, कुमेश कुंजाम, सितु मंडावी, लांचा पुनेम, विज्जा पुनेम, इम्तियाज अली, मंगली सोढ़ी, रिशू पुनेम, रमेश ओयाम, लक्ष्मण ओयाम, बोटी ओयाम, गड़िया कुंजाम, सुदरू कारम और माड़वी आयता के परिवारों को मिलेगा। वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री

केदार कश्यप के मार्गदर्शन में पीड़ित परिवारों को समय पर राहत और पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता देना है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद पुनर्वास नीति के तहत नक्सली पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए सुरक्षा, आर्थिक सहायता और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह पहल प्रभावित परिवारों के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशील सोच और पुनर्वास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

सेन समाज सनातन परंपराओं और सामाजिक समरसता का मजबूत आधार : सीएम साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सेन समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। इस समाज ने सदियों से भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था, संस्कारों और समरसता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेता का इस समाज से होना पूरे सेन समाज के लिए गौरव की बात है। सेन समाज केवल अपनी पारंपरिक सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जन्म से लेकर विवाह और मृत्यु तक समाज के प्रत्येक संस्कार में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह समाज सनातन परंपराओं और संस्कारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री साय आज राजधानी रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित सेन शक्ति सम्मेलन एवं केश शिल्पी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सेन समाज को सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सेन समाज के कल्याण के लिए केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का गठन पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। उन्होंने कहा कि सेन समाज और अन्य पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उस समय अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई। सैलून संचालन के लिए सेन समाज के लोगों को किट, कुम्हारों को बैटरी चलित चाक और बढ़ई समाज के लोगों को कारपेंट्री किट देने की शुरुआत भी इसी दिशा में की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेन समाज की आज की आवश्यकताओं और मांगों पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करेगी।

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि संत शिरोमणि सेन महाराज के नाम पर नया रायपुर में चौक का नामकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नामकरण के लिए कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने सेन समाज के विकास और कल्याण के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुनर और प्रतिभा का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर वंचित वर्गों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक रहे हैं। आज उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी सेन समाज से विधायक रिकेश सेन और छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन समाज की सेवा और प्रदेश के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं।

युवा प्रतिभाओं का इंतजार कर रहे एआई, डेटा सेंटर, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्र: पीएम मोदी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा सेंटर, क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी एक्सप्लोरेशन, बैटरी, पावर स्टोरेज, एनर्जी सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे अनेक क्षेत्र देश के युवाओं की प्रतिभा, नवाचार और नेतृत्व का इंतजार कर रहे हैं।

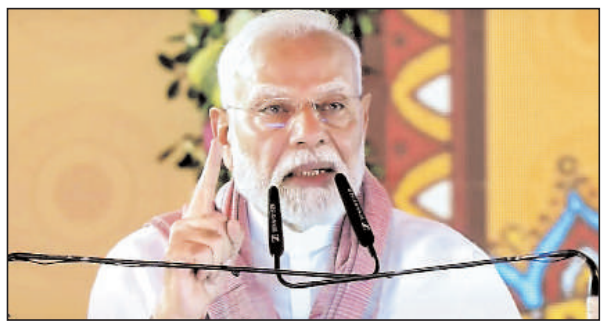

मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ऐसे समय में विकसित भारत की यात्रा पर आगे बढ़ रहा है जब दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी ताकत प्रौद्योगिकी की गति है। उन्होंने कहा कि आने वाले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, यह निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता, लेकिन बदलाव के दौर में चुनौतियों के साथ नये अवसर भी पैदा होते हैं। उन्होंने कहा, दुनिया बदलेगी, प्रौद्योगिकी भी बदलेगी, उद्योग बदलेगा, पेशे भी बदलेंगे।

लेकिन, इन सबके बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा, वह जीतेगा। जो नयी चुनौतियों के नये उपाय खोजने का साहस रखेगा, चुनौतियां उसके लिए अवसर बन जाएंगे। मोदी ने कहा कि आईआईटी से मिलने वाली डिग्री केवल परीक्षा पास करने, अच्छा सीजीपीए हासिल करने या अच्छा प्लेसमेंट पाने का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि विद्यार्थी कठिन समस्याओं का समाधान करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में जब कोई चुनौती बड़ी लगे तो उससे घबराने के बजाय उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर समाधान तलाशना चाहिए।

मोदी ने कहा कि देश के युवाओं के सामने आने वाले वर्षों में नई तकनीकों और क्षेत्रों में काम करने के व्यापक अवसर होंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार की आधुनिक नीतियों के कारण ऐसे कई क्षेत्र युवाओं के लिए खुले हैं, जहां पहले प्रवेश के अवसर सीमित थे और देश में नये-नये क्षेत्र भी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की भूमिका बड़ी है और देश का युवा जितना सशक्त होगा, देश उतना ही सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि आज भारत आर्थिक आत्मनिर्भरता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और औद्योगिक आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रहा है और युवाओं को इस मजबूत नींव पर विकसित भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में युवाओं के लिए नये अवसरों का एक उदाहरण अंतरिक्ष क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक इस क्षेत्र में लगभग पूरा काम सरकार के स्तर पर होता था, लेकिन आज यही क्षेत्र हजारों युवाओं के लिए नये अवसरों का क्षेत्र बन चुका है।

युवा अपने लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं और रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी भारत ने नयी शुरुआत की है और पहली सेमीकंडक्टर इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि चिप से लेकर शिप तक सब कुछ भारत में युवाओं के हाथों से बनेगा।

अगस्त का बिजली बिल भी पिछले पांच माह जैसे बेतहाशा आया है : दीपक बैज

रायपुर। बिजली विभाग झूठा दावा कर रहा है कि अगस्त माह में जो जुलाई के बिजली बिल भेजे गये है उसमें बिजली की खपत कम हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हकीकत यह है कि आम आदमी का बिजली बिल अगस्त माह में जो आया है उसकी राशि भी अप्रैल, मई, जून, जुलाई के जैसे ही लगभग उतनी ही आई है। सरकार और विद्युत कंपनियां जनता को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस के जन आंदोलन से घबरा कर सरकार और बिजली कंपनी अब ज्यादा बिजली बिल भेजने के बाद जनता को ही झूठा ठहरा रही है। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी कर रही भाजपा सरकार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बिजली कंपनी दावा कर रही है कि जून की अपेक्षा जुलाई में 30

प्रतिशत बिजली कम खपत हुई है, लेकिन पिछले 8 माह से प्रतिमाह हर आदमी की औसत बिजली खपत तथा बिजली बिल 30 से 40 प्रतिशत बढ़ते गया है। जो 8 माह में चार गुना से भी ज्यादा है। जून की अपेक्षा जुलाई में खपत कम होना स्वाभाविक है लेकिन बिजली कंपनी पिछले 8 माह के बिजली बिल का विश्लेषण जारी करे। इनके दावे भ्रामक, झूठे और परेशान जनता को मुंह चिढ़ाने वाले है एक तरफ जनता को लूट रहे ऊपर से जनता को ही गलत ठहरा रहे है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विद्युत कंपनी के द्वारा बिजली के दाम नही बढ़ने और बिजली सस्ती होने का दावा जनता के कटे पर नमक छिड़कने वाला है। ढाई साल में भाजपा की सरकार ने बिजली के दाम में 5 बार बढ़ोतरी किया है। 400 यूनिट हाफ योजना बंद कर दिया उसके बाद यह कहना कि बिजली सस्ती हो गयी यह बताता है कि भाजपा सरकार और बिजली कंपनी प्रदेश की जनता को मुर्ख समझती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जनता बढ़े बिजली बिल के कारण परेशान है, लोगों के राशन के बिल से ज्यादा महीने का बिजली बिल आ रहा है। सरकार ऊपर से झूठ बोल रही कि बिजली सस्ती हो गयी है।

सर्वसम्मति से 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून लागू करे सरकार : राहुल गांधी

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है और कांग्रेस ने इसका पूर्ण समर्थन किया था। गांधी ने शनिवार को

सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा, रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर यह कौन जानता होगा-महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ। उन्होंने सवाल किया कि तीन साल बाद भी वह लागू क्यों नहीं हुआ।

अमेरिका के सीनियर मिलिट्री कमांडर ने व्हाइट हाउस से ईरान के साथ टकराव खत्म करने की अपील की

वॉशिंगटन। अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन कई हफ्तों से व्हाइट हाउस से ईरान के साथ टकराव खत्म करने का कोई रास्ता निकालने की अपील कर रहे हैं। सीएनएन ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। एक सूत्र ने कहा, केन इस मामले से बाहर निकलने का रास्ता (ऑफ- रैम्प) ढूंढ रहे हैं। टीवी चैनल के मुताबिक

जनरल केन ने हाल के हफ्तों में कैबिनेट के अहम सदस्यों (जिनमें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो और सीआईए के निदेशक जॉन रैटक्लिफ शामिल हैं) के साथ कई गोपनीय बैठकें की हैं। इन बैठकों का मकसद अपनी राय में तालमेल बिठाना और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के मामले में तनाव और बढ़ाने से जुड़े जोखिमों और गतिरोध के बारे में बताना था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सेना और खुफिया समुदाय में यह समझ बढ़ रही है।

गिरगिट की तरह रंग बदलती है सपा: मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि सपा अपनी संकीर्ण जातिवादी राजनीति और चुनावी स्वार्थ के लिए लगातार राजनीतिक रंग बदलती रही है। मायावती ने 'एक्स' पर जारी सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, बसपा 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की नीति एवं सिद्धांत पर अमल करने वाली

सर्वसमाज हितैषी अंबेडकरवादी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में चार बार उसकी सरकार भी इसी आधार पर चली है। इसके विपरीत सपा अपनी संकीर्ण जातिवादी राजनीति और चुनावी स्वार्थ के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। उन्होंने कहा, इसी क्रम में सपा द्वारा प्रचारित कथित 'पीडीए' अर्थात पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक में पहले 'पी' से 'पिछड़े' का प्रचार करने के बाद अब अपर कास्ट समाज, खासकर ब्राह्मण समाज को बसपा से तेजी से जुड़ता देखकर और उसी आधार पर पार्टी उम्मीदवार बनाए जाने से विचलित होकर सपा ने 'पी' से 'पंडित' कर दिया है।

एनटीए के तीन विषय विशेषज्ञों का नीट-यूजी 2026 परीक्षा में प्रश्नों के लीक में हाथ रहा : सीबीआई

पुणे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से जुड़े तीन विषय विशेषज्ञों पी.वी. कुलकर्णी (रसायन विज्ञान), मनीषा हवलदार (भौतिकी), और मनीषा मंधारे (वनस्पति विज्ञान और प्राणीशास्त्र) की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी 2026) परीक्षा पेपर से प्रश्नों के कथित लीक में हाथ रहा है। सीबीआई ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में विशेष अदालत में 13 आरोपियों के खिलाफ 94 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। जांचकर्ताओं ने बायोमेट्रिक डेटा, मोबाइल कॉल-डिटेल रिकॉर्ड और स्थान विश्लेषण के अलावा हाउसिंग सोसाइटी के एक्सेस-कंट्रोल एप्लिकेशन के

रिकॉर्ड पर बहुत अधिक भरोसा किया है, जहां पुणे स्थित आरोपी कुलकर्णी रहता था। आरोपपत्र में बताया गया है कि कैसे तीन विशेषज्ञों ने कथित तौर पर एनटीए के गोपनीय अनुभाग में सुरक्षा चूक का फायदा उठाया। सीबीआई के अनुसार गोपनीय अनुभाग के लिए कोई समर्पित प्रत्यक्ष-रिकॉर्डिंग नियंत्रण इकाई नहीं थी, जिससे आरोपी विशेषज्ञों की गतिविधियों पर काफी हद तक निगरानी नहीं रखी जा सकी। कथित तौर पर परिसर में प्रवेश करते या बाहर निकलते समय कर्मियों की तलाशी की कोई व्यवस्था नहीं थी। एजेंसी ने दावा किया है कि इन खामियों के कारण प्रश्नपत्र तक पहुंचने और लीक होने का अवसर उत्पन्न हुए। उन्होंने बताया कि मंधारे वनस्पति विज्ञान के पेपर का अंग्रेजी से मराठी में अनुवाद करने और प्राणीशास्त्र के पेपर का दोबारा अनुवाद करने के लिए जिम्मेदार थी, ने कथित तौर पर अपने होटल लौटने के बाद एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों से प्रासंगिक अंशों को चिह्नित किया। सीबीआई ने दावा किया है कि उसके अनुभव ने उसे परीक्षा के प्रश्नों को पाठ्यपुस्तक सामग्री के साथ आसानी से जोड़ने में सक्षम बनाया।

आरोपपत्र के अनुसार हवलदार को भौतिकी अनुवाद का काम सौंपा गया था, कथित तौर पर प्रत्येक दिन के अंत में दिल्ली में अपने आवास पर लौटने के बाद प्रश्नों के संक्षिप्त नोट्स बनाती थी।

सीबीआई ने आगे आरोप लगाया है कि लीक हुआ प्रश्नपत्र पुणे की ब्यूटीशियन मनीषा वाघमारे ने बिचौलियों के माध्यम से राजस्थान और हरियाणा तक पहुंचाया था। कथित तौर पर एक छात्र तक पहुंचने से पहले बिचौलियों की एक श्रृंखला के माध्यम से पेपर को पर्याप्त रकम में बेच दिया गया था। एनटीए में छात्र की शिकायत ने कथित पेपर लीक को प्रकाश में लाने में मदद की।

हवाई अड्डों की साइबर सुरक्षा होगी अभेद्य सीआईएसएफ ने आईआईटी रोपड़ के साथ मिलाया हाथ

नयी दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तथा साइबर सुरक्षा को और

अधिक मजबूत एवं अभेद्य बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी रोपड़ के साथ एक अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते के तहत सीआईएसएफ के जवानों को साइबर सुरक्षा में निपुण बनाने के लिए छह सप्ताह की विशेष आवासीय ट्रेनिंग दी जायेगी। सीआईएसएफ ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। पुलिस महानिदेशकों के 2024 में हुए सम्मेलन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस संगठनों में एक समर्पित 'साइबर कमांडो' कैडर विकसित करने पर जोर दिया गया था। सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन के नेतृत्व में, बल ने उभरते हुए साइबर खतरों को पहचानने, उनसे निपटने और उनका त्वरित समाधान करने के लिए विशेष जवानों की एक टीम तैयार करने का बीड़ा उठाया है।

वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल 24 आईएफएस अधिकारियों का

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 24 आईएफएस अधिकारियों का तबादला किया है। जारी आदेश के अनुसार गणवीर धम्मशील को बलौदाबाजार जिले से हटाकर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उत्तम कुमार गुप्ता को इंद्रावती टाइगर रिजर्व का प्रभारी सीसीएफ बनाया गया है। दुलेश्वर प्रसाद साहू को मनेन्द्रगढ़ वनमंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि पंकज राजपूत को रायपुर का नया वन उप संरक्षक बनाया गया है।

प्रभाकर खलखो को सरगुजा कार्य आयोजना वनमंडल का प्रभारी वन संरक्षक नियुक्त किया गया है। संदीप बलगा को पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल की जिम्मेदारी दी गई है। मयंक पाण्डेय गरियाबंद के वन उप संरक्षक बनाए गए हैं। सत्यदेव शर्मा को धरमजयगढ़ वनमंडल और श्रीनिवास तन्नेटी को महासमुंद के वन उप संरक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जितेन्द्र कुमार उपाध्याय की नवीन पदस्थापना छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में की गई है। संजय यादव को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में प्रतिनियुक्ति दी गई है। कुमार निशांत को खैरागढ़ वनमंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंकज कुमार कमल को मरवाही वनमंडल का वन उप संरक्षक, पुष्पलता टंडन को सारंगढ़-बिलाईगढ़ की वन उप संरक्षक और लोकनाथ पटेल को सरगुजा वनमंडल की जिम्मेदारी दी गई है। शषिगानंदन के. को कांकेर का वन उप संरक्षक बनाया गया है। अभिषेक जोगावत को लघु वनोपज संघ में उप महाप्रबंधक की जिम्मेदारी दी गई है। रौनक गोयल को पीसीसीएफ कार्यालय में वन उप संरक्षक बनाया गया है। ग्रीष्मी चांद को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में प्रतिनियुक्ति दी गई है। चंद्रशेखर परदेशी कोरिया के वन उप संरक्षक बनाए गए हैं। दिपेश कपिल को बस्तर वनमंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंद्र कुमार अग्रवाल को दुर्ग का वन उप संरक्षक बनाया गया है।

संभाग स्तरीय कुश्ती में शंकरगढ़ का जलवा, 7 पहलवानों ने जीते स्वर्ण पदक

शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, विद्यालय पहुंचने पर हुआ सम्मान

शंकरगढ़/मूक पत्रिका

दुर्गेश गुप्ता - संभाग स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शंकरगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सात स्वर्ण पदक हासिल किए। युवा पहलवानों की इस उपलब्धि से विद्यालय सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। खिलाड़ियों ने अपने-अपने भार वर्ग में बेहतरीन दांव-पेंच का प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में दबदबा बनाया।प्रतियोगिता में अन्वेंशन कुमार ने 45 किग्रा फ्री स्टाइल, प्यारेलाल तिर्की ने 45 किग्रा ग्रीको रोमन, अमन कुजूर ने 48 किग्रा, विपिन पैंकरा ने 50 किग्रा, विकास पैकरा ने 55 किग्रा, नरेन्द्र कुमार ने 60 किग्रा तथा उमेश पैकरा ने 64 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

खिलाड़ियों का किया गया सम्मान- प्रतियोगिता में जीत के बाद विद्यालय लौटे खिलाड़ियों का प्राचार्य एवं शिक्षकों ने जोरदार स्वागत किया। प्राचार्य सुशील कुमार एक्का सहित विद्यालय के समस्त स्टाफ ने खिलाड़ियों को गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया और मुंह मीठा कराया। शिक्षकों ने खिलाड़ियों को भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर शिक्षक सुदर्शन यादव ने कहा कि शंकरगढ़ क्षेत्र प्रतिभाओं से भरा हुआ है। बच्चों को सही दिशा और प्रशिक्षण मिलने पर वे खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं।

कुश्ती के गद्दे मिलने से मिला बेहतर अभ्यास-प्राचार्य सुशील कुमार एक्का ने खिलाड़ियों की सफलता का श्रेय खेल शिक्षकों के मार्गदर्शन और लगातार अभ्यास को देते हुए सामरी विधायक श्रीमती उदेश्वरी पैकरा एवं जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती प्रियंवदा सिंह देव के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विद्यालय को रेसलिंग मैट उपलब्ध होने से खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर सुविधा मिली है। प्राचार्य ने कहा कि विद्यालय के विद्यार्थी सरगुजा ओलंपिक सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ खेल शिक्षकों एवं सुदर्शन यादव के प्रयासों की भी सराहना की। सम्मान समारोह में शोभन भट्टाचार्य, बलदेव प्रसाद सोनवानी, मंगल तिर्की, सीता भास्कर राव, अनुपा एक्का, अनीश तिर्की, अमितेश यादव, लक्ष्मीकांत सिन्हा, कामेश्वरी पैकरा, शालिनी सोनी, आकांक्षा यादव, मीरा, दिव्या, आनंदी, प्रियंका, विराग गुप्ता सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरिया में हुआ वृक्षारोपण, छात्राओं ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

महिला पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान के संयुक्त तत्वावधान में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरिया में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वस्थ और हरित भारत का संदेश देना रहा। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के फलदार एवं उपयोगी पौधे लगाए गए।कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य पुरुषोत्तम चौधरी, नगर पंचायत सरिया अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, भारत स्वाभिमान एवं महिमा आश्रम योग समिति से योग गुरु त्रिलोक गोयल, सुरेश प्रधान, पूर्व शिक्षिका सी. सोरेंग, ग्राम पंचायत नदीगांव के सरपंच गौरीशंकर विश्वाल, सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पांजलि बिस्वाल, महिला पतंजलि योग समिति की जिला सोशल मीडिया प्रभारी नीलावती डनसेना सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

इसके अलावा महिला पतंजलि योग समिति जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ की योग शिक्षिका यज्ञसैनी प्रधान, कन्या माध्यमिक शाला सरिया के प्रधान पाठक नरेश प्रधान सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भी पौधरोपण में भाग लिया। छात्राओं ने उत्साह के साथ पौधे लगाए और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी लेने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण असंतुलन को देखते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना समय की जरूरत है। नगर पंचायत सरिया अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में चल रहे पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी अभियान के तहत विद्यालय परिसर में भी पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए नियमित रूप से पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संदेश दिया।

आदिवासी कांग्रेस कमेटी का सारंगढ़-बिलाईगढ़ में विस्तार, 7 ब्लॉकों में अध्यक्षों की नियुक्ति, सरिया की कमान राजकुमार सिदार को..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

जिला आदिवासी कांग्रेस कमेटी ने संगठन को मजबूत करने के लिए जिले के विभिन्न ब्लॉकों में नए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की है। जिला अध्यक्ष सहदेव सिंह सिदार द्वारा जारी आदेश के तहत जिले के सात संगठनात्मक क्षेत्रों में अध्यक्षों की जिम्मेदारी तय की गई है।

इन ब्लॉकों में हुई नियुक्ति- जारी सूची के अनुसार सारंगढ़ शहर में विजय सिदार, सारंगढ़ ग्रामीण में दिलेश्वर सिदार, बरमकेला में बाबूलाल सिदार, उल्लेखर कोसीर में रवि सिदार, बिलाईगढ़ में किशोर कुमार सिंह, सरसीवा में विजय सिदार और सरिया में राजकुमार सिदार को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। संगठन की ओर से उम्मीद जताई गई है कि नवनियुक्त अध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के साथ ही कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे और कांग्रेस की गतिविधियों को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे।

सरिया ब्लॉक की जिम्मेदारी राजकुमार सिदार को-सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सरिया ब्लॉक में बुदबुदा निवासी राजकुमार सिदार को आदिवासी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

उनकी नियुक्ति के बाद अब सरिया क्षेत्र में संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय कर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। जिला आदिवासी कांग्रेस कमेटी के अनुसार यह नियुक्तियां संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से की गई हैं।

15 अगस्त तक मांगों का समाधान नहीं तो 17 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना, ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

क्षेत्र की वर्षों पुरानी मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ग्राम पंचायत सरसभांठा एवं बालपुर के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि 15 अगस्त 2026 तक उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो 17 अगस्त 2026 से ग्रामीण लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे। ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग पेड्रावन सरसभांठाङ्कबालपुर कोसिर मार्ग के लगभग 7 किलोमीटर लंबे जर्जर सड़क मार्ग का निर्माण है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। बरसात के दिनों में कीचड़ और जलभराव के कारण स्कूली बच्चों, किसानों, मरीजों और आम लोगों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने तथा तब तक सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। दूसरी प्रमुख मांग बालपुर स्थित स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन निर्माण से जुड़ी है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय भवन के लिए शासन से 1 करोड़ 21 लाख 16 हजार रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके कारण 500 से अधिक छात्र-छात्राओं को असुविधाजनक परिस्थितियों में पढ़ाई करनी पड़ रही है।ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य के दौरान बनाए गए पुल के बाद निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया था। वहीं, बायपास सड़क निर्माण से प्रभावित किसानों का मुआवजा भी एसडीएम कार्यालय में लंबित है। ग्रामीणों ने प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा राशि वितरित कर सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन को स्पष्ट अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि 15 अगस्त तक उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो 17 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन के साथ पंचायत प्रस्ताव, जर्जर सड़क की तस्वीरें तथा विद्यालय भवन की स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं।

नकली सोने का हार असली बताकर ग्रामीण से 10 हजार की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

नगरनार/जगदलपुर/मूक पत्रिका

थाना नगरनार क्षेत्र में नकली सोने के हार को असली बताकर ग्रामीण से 10 हजार रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से ठगी की रकम समेत नकली सोने की तीन मालाएं और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार, मंगनपुर निवासी लिंगेश्वर सेठिया ने थाना नगरनार में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 6 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे वह काम से जगदलपुर जाने के लिए घर से निकल रहा था। इसी दौरान दो व्यक्ति उसके घर पहुंचे।

इनमें से एक ने अपना नाम मोहन लाल सोलंकी निवासी भिलाई-दुर्ग बताया और पैसों की जरूरत बताते हुए करीब पांच लाख रुपये कीमत का सोने का हार होने की बात कही।आरोपी ने हार दिखाकर ग्रामीण से 10 हजार रुपये तत्काल देने की मांग की और शेष राशि अगले दिन देने की बात कही। ग्रामीण ने 10 हजार रुपये देकर हार अपने पास रख लिया। बाद में जब उसने हार को सोनार की दुकान पर जांच कराया तो वह असली सोना नहीं, बल्कि पीतल मिश्रित नकली हार निकला। इसके बाद पीड़ित ने नगरनार थाने में शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 117/2026, धारा 318(4), 35 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने तलाश के बाद मोहन लाल सोलंकी (52) निवासी नेहरू चौक, चरौदा, थाना भिलाई-3, जिला दुर्ग और मोहन राय (52) निवासी हथनीपारा वार्ड, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार को गिरफ्तार किया।पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपराध करना स्वीकार किए जाने की बात पुलिस ने कही है। आरोपियों के कब्जे से 4,950 रुपये नकद, तीन नग नकली सोने की माला (कुल वजन 342.190 ग्राम) और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर के दिशा-निर्देशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक सुमीत कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक विकेश तिवारी के नेतृत्व में की गई।

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटा प्रशासन, कलेक्टर ने स्टेडियम पहुंचकर देखी व्यवस्थाएं

अधिकारियों को समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश

बीजापुर/मूक पत्रिका

/आशीष पदमवार। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला मुख्यालय के इंदिरा मिनी स्टेडियम में होने वाले मुख्य समारोह की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर विश्वदीप ने शुक्रवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर चल रही तैयारियों को देखा और संबंधित अधिकारियों से अब तक की व्यवस्था की जानकारी ली। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय पर्व के आयोजन में किसी तरह की अव्यवस्था या कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय से निर्धारित समय में तैयारियां पूरी करें।निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मुख्य मंच की व्यवस्था, अतिथियों एवं आमंत्रितों के लिए बैठक व्यवस्था, परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा इंतजाम, विद्युत व्यवस्था और पेयजल सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों को समय-सीमा में पूरा करने के साथ तैयारियों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।

हर व्यवस्था पर रहेगी नजर- कलेक्टर विश्वदीप ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस जिला मुख्यालय का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। समारोह में बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल होते हैं। ऐसे में कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित और बेहतर होना जरूरी है।

उन्होंने विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने तथा अंतिम समय में किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए सभी तैयारियां पहले से पूरी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत की सीईओ नम्रता चौबे,एसडीएम जागेश्वर कौशल,डीईओ राजेश पांडेय सहित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पूर्व DFO पुष्पलता टंडन की जिले में दोबारा पदस्थापना, शासन ने 24 IFS अधिकारियों के तबादले का जारी किया आदेश

सारंगढ़-बिलाईगढ़ में फिर बदली वन विभाग की कमान, विपुल अग्रवाल सूरजपुर ट्रांसफर

बरमकेला/मूक पत्रिका

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने शनिवार को भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है। प्रदेश में किए गए इस प्रशासनिक फेरबदल में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के वन विभाग में भी बदलाव किया गया है। जिले में वन उप संरक्षक (क्षेत्रीय) के पद पर पदस्थ विपुल अग्रवाल का स्थानांतरण सूरजपुर कर दिया गया है। उनके स्थान पर पूर्व में सारंगढ़-बिलाईगढ़ में छ्न्नह की जिम्मेदारी संभाल चुकीं पुष्पलता टंडन की पुनः पदस्थापना की गई है। 8 अगस्त 2026 को जारी शासन के आदेश के अनुसार विपुल अग्रवाल, भारतीय वन सेवा 2022 बैच के अधिकारी हैं। वे वर्तमान में सारंगढ़-बिलाईगढ़ के वन उप संरक्षक (क्षेत्रीय) के रूप में पदस्थ थे। शासन ने उन्हें अब वन उप संरक्षक (क्षेत्रीय), सूरजपुर के पद पर पदस्थ किया है। वहीं 2016 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी पुष्पलता टंडन को वन उप संरक्षक (क्षेत्रीय), सारंगढ़-बिलाईगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है।

पूर्व अनुभव के साथ जिले में वापसी-पुष्पलता टंडन की नई पदस्थापना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वे इससे पहले सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में छ्न्नह की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। यानी जिले के वन प्रशासन और यहां की परिस्थितियों से वे पहले से परिचित रही हैं। शासन के ताजा आदेश में उन्हें वर्तमान पदस्थापना से हटाकर पुनः सारंगढ़-बिलाईगढ़ भेजा गया है। इससे जिले में वन विभाग की जिम्मेदारी एक ऐसे अधिकारी के हाथों में जाएगी, जिन्हें यहां काम करने का पूर्व अनुभव भी है। टंडन की वर्तमान पदस्थापना वन उप संरक्षक (वन्यजीव) कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यजीव वार्डन, अरण्य भवन, नवा रायपुर में थी। शासन ने उन्हें वहां से स्थानांतरित कर सारंगढ़-बिलाईगढ़ का वन उप संरक्षक (क्षेत्रीय) बनाया है।

वन क्षेत्र और संरक्षण से जुड़े काम होंगे अहम-सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में वन विभाग की भूमिका केवल प्रशासनिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है। जिले के वन क्षेत्रों का प्रबंधन, वन संरक्षण, वन्यजीवों से जुड़े विषय, विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन और वन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न कार्य छ्न्नह स्तर के अधिकारियों की निगरानी में संचालित होते हैं। ऐसे में छ्न्नह का स्थानांतरण जिले के वन प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण बदलाव माना जाता है। नई छ्न्नह के रूप में पुष्पलता टंडन के सामने जिले में वन विभाग के नियमित प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ विभागीय गतिविधियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। हालांकि शासन के आदेश में उनके आगामी कार्यों या किसी विशेष प्राथमिकता का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इस संबंध में फिलहाल कोई आधिकारिक दावा नहीं किया जा सकता।

प्रदेश में 24 द्वस्र अधिकारियों का प्रशासनिक फेरबदल-वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश में कुल 24 भारतीय वन सेवा अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की गई है। आदेश में अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के सामने दर्शाए गए नवीन पदस्थापना स्थल पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया है। स्थानांतरण सूची में अलग-अलग वन मंडलों और विभागीय पदों पर कार्यरत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसी सूची में सारंगढ़-बिलाईगढ़ और सूरजपुर से संबंधित बदलाव भी शामिल है।

विपुल अग्रवाल की नई जिम्मेदारी सूरजपुर में-सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पदस्थ विपुल अग्रवाल अब सूरजपुर वन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे।

शासन के आदेश में उनकी वर्तमान पदस्थापना सारंगढ़-बिलाईगढ़ और नवीन पदस्थापना सूरजपुर दर्ज की गई है। वहीं, जिले में उनकी जगह पुष्पलता टंडन की पदस्थापना से सारंगढ़-बिलाईगढ़ वन विभाग को नया प्रशासनिक नेतृत्व मिलेगा। टंडन की पहले की पदस्थापना को देखते हुए यह बदलाव जिले के वन विभाग के लिए खासा महत्वपूर्ण है।

SECL धरमखदान में ट्रांसफार्मर पाट्र्स व केबल चोरी का 24 घंटे में खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार, 3 लाख का मशरूका बरामद

रायगढ़ /मूक पत्रिका

रायगढ़ पुलिस को संपत्ति संबंधी अपराधों में लगातार सफलता मिल रही है, इसी कड़ी में छाल पुलिस ने स्श्वष्टरु धरमखदान में ट्रांसफार्मर के पाट्र्स, केबल, पानी पंप के पाट्र्स एवं लोहे के पाइप चोरी के मामले का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी का लगभग ?1.20 लाख का सामान तथा घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल सहित कुल करीब ?3 लाख का मशरूका बरामद किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी खरसिया श्री सतीश भार्गव के सुपरविजन में छाल पुलिस को चोरी के मामले में यह महत्वपूर्ण सफलता मिली है। चोरी को लेकर प्रार्थी दिलीप कुमार राठिया, सुरक्षा प्रहरी स्श्वष्टरु छाल उपक्षेत्र, द्वारा कल थाना छाल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 06 अगस्त 2026 की रात्रि करीब 8 बजे से 11 बजे के मध्य धरमखदान में लगे ट्रांसफार्मर के पाट्र्स, ट्रांसफार्मर केबल, पानी पंप के पाट्र्स एवं लोहे के पाइप, कुल कीमत करीब ?1,20,000, अज्ञात आरोपियों द्वारा चोरी कर लिए गए तथा ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। रिपोर्ट पर थाना छाल में अप.क्र. 185/2026, धारा 303(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।मामले की गंभीरता को देखते हुएएसडीओपी खरसिया श्री सतीश भार्गव के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी छाल निरीक्षक नासिर खान द्वारा तत्काल टीम गठित कर आरोपियों एवं चोरी गए माल की पतासाजी शुरू की गई। इसी दौरान पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि खेदापाली चौक के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति लोहे के पाइप, ट्रांसफार्मर केबल एवं अन्य लोहे का सामान बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 6 संदिग्धों को पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम दीपक पात्रो, शनिचराम अरमु, छतन धनवार, रूपभवन सिंह उइके, टुपाल सिंह मरावी एवं भारत सिंह मरकाम बताया। आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने 06 अगस्त की रात धरमखदान से ट्रांसफार्मर के पाट्र्स, केबल, पानी पंप की बॉडी एवं लोहे के पाइप चोरी करना तथा चोरी के सामान को आपस में बांट लेना स्वीकार किया। आरोपियों ने चोरी का सामान एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिलों को चंद्रशेखरपुर (एडू) स्थित धरमखदान डम्पिंग यार्ड के पीछे मॉड नदी के किनारे छिपाकर रखना बताया। आरोपियों के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर प्रकरण में संगठित अपराध संबंधी धारा 112(2) एवं 3(5) बीएनएस जोड़ी गई। आरोपियों की निशानदेही पर छाल पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर चोरी का सामान बरामद किया। शनिचराम अरमु के कब्जे से लोहे के पाइप एवं ट्रांसफार्मर केबल वायर, दीपक पात्रो के कब्जे से लोहे के पाइप एवं ट्रांसफार्मर केबल वायर तथा घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल क्रमांक छ्त्त-12-क्ष्ख्र-2410 एवं आरीपत्ती ब्लेड, भारत सिंह मरकाम के कब्जे से लोहे के पाइप एवं घटना में प्रयुक्त बजाज छ्र्ञ-100 मोटरसाइकिल क्रमांक छ्त्त-12-2131, टुपाल सिंह मरावी के कब्जे से लोहे के पाइप एवं घटना में प्रयुक्त ॥स्न छ्द्गद्यह्न×द्ग मोटरसाइकिल क्रमांक छ्त्त-12-7419, रूपभवन सिंह उइके के कब्जे से पानी पंप की लोहे की बॉडी 2 नग तथा छतन धनवार के कब्जे से ट्रांसफार्मर के एंगल 2 नग बरामद कर विधिवत जप्त किए गए।

निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारियों की समस्याओं पर श्रम पदाधिकारी के साथ हुई बैठक कई मुद्दों पर हुआ निर्णय

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/ कांकेर नगर पालिका के प्लेसमेंट कर्मचारियों के विभिन्न समस्याओं को लेकर कल श्रम पदाधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अलर्ट सिक्युरिटी ब्यूरो के मालिक एवं यूनियन के साथ श्रम विभाग के दफ्तर में बैठक हुई। बैठक की जानकारी देते हुए यूनियन के इकाई महासचिव दिलीप साहू ने बताया कि कर्मचारियों का वेतन भुगतान निर्धारित निश्चित समय पर नहीं होना, साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलना, अतिरिक्त कार्य का ओवरटाइम न मिलना, ई एसआई कार्ड के सभी त्रुटियों को नहीं सुधारना, सलाना बोनस भुगतान की मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान यूनियन के प्रतिनिधियो ने अपना मांग किया कि श्रम कानून के तहत प्रत्येक माह के 7 तारीख तक समय पर वेतन भुगतान निश्चित किया जाए अन्यथा विलंब की स्थिति में श्रम कानून के मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत प्रतिकर के साथ भुगतान किया जाए। इसके साथ इस मांग को भी रखा कि साप्ताहिक अवकाश के बदले कार्य के दिवस का ओवरटाइम की राशि भुगतान किया जाए, ई एसआई कार्ड के सभी त्रुटियों को सुधार कर अविलंब सुधार कर वितरित किया जाए। यूनियन के इन सभी शिकायतों और मांगों को श्रम पदाधिकारी ने सही पाया है। जिस पर श्रम पदाधिकारी ने अलर्ट सिक्युरिटी ब्यूरो को निर्देशित किया कि प्रत्येक माह के 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाए। आगामी 27 अगस्त तक ई एसआई कार्ड के सभी त्रुटियों को सुधार कर वितरित किया जाए।

सभी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश और अवकाश पर कार्य कराने का ओवरटाइम भुगतान के बारे में सकारात्मक विचार हो। यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में भाव सिंह कश्यप, द्वारका कोसरिया, रेखा बाल्मीकि, कुसुम बाल्मीकि, अरुण वाल्मीक, राकेश बिछिया, प्रशांत रजक, राज रजक, ओम कुमारी, संतोष नेताम प्रमुख रूप से मौजूद थे।

ट्रांसफार्मर का बोर्ड खुला, नीचे झूल रहे बिजली के तार से हादसे का खतरा

बरसात के मौसम में बिजली विभाग की लापरवाही उजागर

रायगढ़/मूक पत्रिका

बरसात के मौसम में बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। महिंद्रा ट्रैक्टर शोरूम के बगल अम्बिका ट्रेडर्स के सामने लगे एक ट्रांसफार्मर का बिजली बोर्ड खुला पड़ा है, जबकि आसपास से गुजर रहे बिजली के तार भी नीचे की ओर झूल रहे हैं।

इससे राहगीरों और ग्रामीणों के लिए गंभीर हादसे का खतरा बना हुआ है।बारिश के दौरान जमीन और आसपास का क्षेत्र गीला होने के कारण खुले विद्युत उपकरण और नीचे झूलते तार किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले की जानकारी संबंधित विभाग को होने के बावजूद अब तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से मांग की है कि ट्रांसफार्मर के खुले बोर्ड को तत्काल बंद किया जाए और नीचे झूल रहे तारों को सुरक्षित ऊंचाई पर व्यवस्थित किया जाए, ताकि बरसात के दौरान किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। लोगों का सवाल है कि आखिर बिजली विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों कर रहा है? समय रहते सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

कोयाबाना आदिवासी संस्कृति संवर्धन संस्थान : विरासत से भविष्य तक की नई पहल-विश्व आदिवासी दिवस पर विशेष

गोंडी भाषा सीख रहे 40 बच्चे, प्रतिदिन 20–25 लोग पहुंच रहे कोयाबाना

संग्रहालय से आगे बढ़कर भाषा, संस्कृति, शोध और सामुदायिक रेडियो का बनेगा केंद्र

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/ कांकेर 9 अगस्त 2026 विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर उत्तर बस्तर कांकेर जिले की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपरा, लोककला, भाषा और विरासत को संरक्षित करने तथा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की दिशा में 'कोयाबाना आदिवासी संस्कृति संवर्धन संस्थान' एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभर रहा है। जिला प्रशासन के सौजन्य से विकसित की जा रही यह पहल केवल एक संग्रहालय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे कांकेर की सांस्कृतिक पहचान, इतिहास, भाषा और लोकज्ञान के जीवंत केंद्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। कांकेर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ समृद्ध आदिवासी जीवनशैली, लोकगीत, लोकनृत्य, पारंपरिक वेशभूषा, आभूषण, कृषि परंपराओं, हस्तशिल्प, लोककथाओं और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की अनूठी संस्कृति के लिए विशिष्ट पहचान रखता है। कोयाबाना इसी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को व्यवस्थित रूप से संजोने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास है। 40 बच्चे सीख रहे गोंडी भाषा कोयाबाना की प्रमुख गतिविधियों में गोंडी भाषा शिक्षण विशेष आकर्षण का केंद्र है। वर्तमान में लगभग 40 बच्चे नियमित रूप से गोंडी भाषा सीख रहे हैं। इसके माध्यम से बच्चों को अपनी भाषा, लोकपरंपराओं और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कोयाबाना की गतिविधियों और प्रदर्शित विरासत को देखने के लिए प्रतिदिन लगभग 20 से 25 लोग पहुंच रहे हैं। विद्यार्थियों, युवाओं, स्थानीय नागरिकों और अन्य आगंतुकों की बढ़ती रुचि इसे एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र का स्वरूप दे रही है। विरासत के विविध रूपों का संरक्षण कोयाबाना में कांकेर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को विभिन्न आयामों में प्रस्तुत किया जा रहा है। यहां ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक विरासत, आदिवासी जीवनशैली, पारंपरिक वस्त्र एवं आभूषण, कृषि उपकरण, लोककला एवं हस्तशिल्प, पारंपरिक आवास और जीवन पद्धति, ऐतिहासिक स्थलों की फोटो गैलरी, गोंडी भाषा तथा स्थानीय लोकज्ञान को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित एवं संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन की सामूहिक सोच का परिणाम कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर के मार्गदर्शन में कोयाबाना को महज प्रदर्शनी स्थल न बनाकर जिले की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने वाले जीवंत संस्थान के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के स्तर पर जनभागीदारी, स्थानीय समुदाय, कलाकारों और विभिन्न संस्थाओं के समन्वय से इसकी गतिविधियों को व्यापक स्वरूप देने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने जिला स्तर पर विद्यार्थियों को स्थानीय इतिहास, आदिवासी संस्कृति, लोककला और गोंडी भाषा से जोड़ने के लिए कोयाबाना को जीवंत शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। भविष्य में विद्यालयीन भ्रमण, सांस्कृतिक गतिविधियों और स्थानीय विरासत आधारित शिक्षण को विस्तार दिया, विद्यार्थियों की सहभागिता तथा स्थानीय ज्ञान को शिक्षा से जोड़ने के लिए आवश्यक समन्वय किया जा रहा है।

निमितेश सिंह ने संभाला एसडीओपी जशपुर का पदभार एसडीओपी जशपुर चंद्रशेखर परमा को भावभीनी विदाई

जशपुरनगर। एसडीओपी जशपुर चंद्रशेखर परमा का स्थानांतरण एसडीओपी सरायपाली के पद पर किया गया है। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाइन), बिलासपुर निमितेश सिंह को एसडीओपी जशपुर के पद पर पदस्थ किया गया है। इसी क्रम पुलिस कार्यालय जशपुर में गरिमामय विदाई एवं स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में चंद्रशेखर परमा को उनके स्थानांतरण पर भावभीनी विदाई दी गई तथा निमितेश सिंह का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें एसडीओपी जशपुर का पदभार ग्रहण कराया गया।इस अवसर पर डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार, जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी, एसडीओपीगण, थाना एवं चौकी प्रभारी तथा पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। विदाई समारोह में उपस्थित अधिकारियों ने चंद्रशेखर परमा के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, जनसंपर्क एवं पुलिसिंग को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनके उत्कृष्ट कार्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए नवीन पदस्थापना हेतु शुभकामनाएं एवं उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएं दीं। बेहतर काम करने की। उम्मीद इस अवसर पर डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने नवपदस्थ एसडीओपी निमितेश सिंह का स्वागत करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके अनुभव एवं नेतृत्व में जशपुर अनुविभाग में कानून-व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि सिंह आमजन से बेहतर संवाद स्थापित करते हुए अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, त्वरित पुलिस कार्रवाई तथा जनहित में उत्कृष्ट पुलिसिंग को प्राथमिकता देंगे।

सुदृढ़ करेंगे व्यवस्था

नवपदस्थ एसडीओपी निमितेश सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यक्त विश्वास के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि वे जशपुर जिले की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने, कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा पुलिस एवं जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करने के लिए पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करेंगे।

गांव-गांव पहुंच रहे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रेमशंकर शुक्ला के साथ सुन रहे जनता की समस्याएं, ग्रामीण बोले- हमारा विधायक कौन है, आज तक हम लोग जानते ही नहीं है देखा ही नहीं है

तोकापाल/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज लगातार चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के गांवों का दौरा कर आम जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। उनके साथ बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) के जिलाध्यक्ष प्रेमशंकर शुक्ला भी लगातार गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों तक बात पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को तोकापाल ब्लॉक के कुरेंगा, कुड़मीगुड़ा, बाघनपाल, पलवा और ऐर्राकोट सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया गया। इस दौरान दीपक बैज और प्रेमशंकर शुक्ला ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं, स्थानीय जरूरतों और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों की जानकारी ली।ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न मूलभूत समस्याओं से नेताओं को अवगत कराया। समस्याएं सुनने के बाद दीपक बैज ने मौके से ही संबंधित अधिकारियों से फोन पर चर्चा की और ग्रामीणों की समस्याओं की जानकारी देते हुए उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ÷जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान कराना हमारी प्राथमिकता है। गांव के लोगों को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के लिए भटकना न पड़े, इसलिए हम स्वयं गांवों तक पहुंचकर उनकी बात सुन रहे हैं। संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं।÷दौरे के दौरान जिलाध्यक्ष प्रेमशंकर शुक्ला ने भी ग्रामीणों से विस्तृत चर्चा की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर समस्याओं की जानकारी साझा की तथा जल्द समाधान की दिशा में पहल की। शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस संगठन जनता के बीच रहकर काम करने में विश्वास रखता है। गांव के अंतिम व्यक्ति की समस्या को सुनना और उसे उचित स्तर तक पहुंचाना संगठन की जिम्मेदारी है। विधायक की गैरमौजूदगी को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी-जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों में स्थानीय विधायक को लेकर नाराजगी की बातें भी सामने आईं। कई ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ÷हमारा विधायक कौन है, हम आज तक देखे ही नहीं हैं। हमारा गांव विधायक जी आया ही नहीं है।÷ ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि के गांव तक पहुंचने का इंतजार है।

बरमकेला, बिलाईगढ़, सरिया और भटगांव में नए तहसीलदार; ओडिशा सीमा से सटे बरमकेला की कमान कोमल प्रसाद साहू को, बिलाईगढ़ में नीलिमा अग्रवाल

जिले में तहसीलदारों के प्रभार में बड़ा फेरबदल, चार तहसीलों में बदली जिम्मेदारी

बरमकेला/मूक पत्रिका

जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने तहसीलदारों की पदस्थापना में फेरबदल किया है। कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार जिले की चार महत्वपूर्ण तहसीलों बरमकेला, सरिया, बिलाईगढ़ और भटगांव में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्यालयीन कार्यों के सुचारु संचालन को ध्यान में रखते हुए किए गए इस फेरबदल के बाद संबंधित तहसीलों में राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी नए अधिकारियों के हाथों में होगी।इस बदलाव में खास बात यह है कि जिले के महत्वपूर्ण ब्लॉक मुख्यालय बरमकेला और बिलाईगढ़ की तहसीलों की जिम्मेदारी क्रमशः कोमल प्रसाद साहू और नीलिमा अग्रवाल को सौंपी गई है। वहीं बरमकेला से पुष्पेन्द्र कुमार राज को सरिया और बिलाईगढ़ से कमलेश कुमार सिदार को भटगांव स्थानांतरित किया गया है। चारों क्षेत्रों की भौगोलिक एवं आर्थिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं, जिसके चलते नई पदस्थापनाओं को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।बरमकेला की जिम्मेदारी कोमल प्रसाद साहू के हाथों में प्रशासनिक फेरबदल में कोमल प्रसाद साहू को बरमकेला तहसीलदार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वे सरिया क्षेत्र में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब उन्हें जिले के एक महत्वपूर्ण और बड़े ब्लॉक मुख्यालय बरमकेला की तहसील की जिम्मेदारी दी गई है।बरमकेला की भौगोलिक स्थिति भी इसे महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि यह क्षेत्र ओडिशा राज्य की सीमा से सटा हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहां प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्व संबंधी कार्यों के प्रभावी संचालन की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही बरमकेला बड़ा ब्लॉक मुख्यालय होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग विभिन्न प्रशासनिक एवं राजस्व कार्यों के लिए यहां पहुंचते हैं। नई जिम्मेदारी के साथ कोमल प्रसाद साहू के सामने तहसील कार्यालय की व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित करने के साथ आम लोगों से जुड़े मामलों के प्रभावी निराकरण की जिम्मेदारी होगी। सरिया में जिम्मेदारी संभालने के बाद अब बरमकेला जैसे बड़े और महत्वपूर्ण ब्लॉक मुख्यालय की जिम्मेदारी मिलने से उनके प्रशासनिक अनुभव का उपयोग क्षेत्र की व्यवस्था को बेहतर बनाने में होने की उम्मीद है।

बिलाईगढ़ की कमान नीलिमा अग्रवाल को-वहीं नीलिमा अग्रवाल को बिलाईगढ़ तहसीलदार बनाया गया है। उन्हें भटगांव से स्थानांतरित कर बिलाईगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिलाईगढ़ भी जिले का एक महत्वपूर्ण ब्लॉक मुख्यालय है और प्रशासनिक एवं राजस्व गतिविधियों की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है।

बिलाईगढ़ क्षेत्र की बड़ी आबादी अपनी विभिन्न प्रशासनिक एवं राजस्व जरूरतों के लिए तहसील मुख्यालय पर निर्भर रहती है। ऐसे में नीलिमा अग्रवाल को बिलाईगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ब्लॉक मुख्यालय की जिम्मेदारी मिलना प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। उनके सामने तहसील कार्यालय की व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के साथ आम नागरिकों से जुड़े मामलों के प्रभावी निराकरण की जिम्मेदारी होगी।

बिलाईगढ़ में नई जिम्मेदारी संभालने के बाद नीलिमा अग्रवाल के सामने क्षेत्र में प्रशासनिक कामकाज को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने और लोगों से जुड़े मामलों के निराकरण को प्राथमिकता देने की चुनौती होगी।

सरिया की जिम्मेदारी पुष्पेन्द्र कुमार राज को–तहसीलदार पुष्पेन्द्र कुमार राज को बरमकेला से स्थानांतरित कर सरिया तहसीलदार बनाया गया है। सरिया क्षेत्र की अपनी अलग आर्थिक एवं औद्योगिक पहचान है। यहां खनिज गतिविधियों के साथ बड़ी संख्या में क्रेशर एवं उनसे संबंधित गतिविधियां संचालित होती हैं।खनिज एवं क्रेशर गतिविधियों वाले क्षेत्र में राजस्व, खनिज और प्रशासन से जुड़े मामलों का प्रभावी संचालन तहसील प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण रहता है। ऐसे में पुष्पेन्द्र कुमार राज के सामने सरिया क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के साथ संबंधित मामलों का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी।

बरमकेला में जिम्मेदारी संभालने के बाद अब सरिया की नई जिम्मेदारी मिलने से उनके सामने क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रशासनिक कार्यों को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी।

भटगांव में कमलेश कुमार सिदार संभालेंगे जिम्मेदारी

इसी फेरबदल के तहत कमलेश कुमार सिदार को बिलाईगढ़ से स्थानांतरित कर भटगांव तहसीलदार बनाया गया है। अब वे भटगांव तहसील में राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे।

चार तहसीलों में नई प्रशासनिक व्यवस्था

कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के बाद जिले में तहसील स्तर पर नई व्यवस्था इस प्रकार होगी–

कोमल प्रसाद साहू – तहसीलदार, बरमकेला

नीलिमा अग्रवाल – तहसीलदार, बिलाईगढ़

पुष्पेन्द्र कुमार राज – तहसीलदार, सरिया

कमलेश कुमार सिदार – तहसीलदार, भटगांव

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में यह फेरबदल प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्यालयीन कार्यों के सुचारु संचालन के लिए किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। संबंधित अधिकारियों को नवीन पदस्थापना के अनुसार कार्यभार ग्रहण कर जिम्मेदारी संभालनी होगी।

चारों तहसीलों में अधिकारियों की नई पदस्थापना के बाद अब राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों के संचालन में भी बदलाव देखने को मिलेगा। खासकर ओडिशा सीमा से सटे बरमकेला, महत्वपूर्ण ब्लॉक मुख्यालय बिलाईगढ़ तथा खनिज और क्रेशर गतिविधियों के लिए पहचाने जाने वाले सरिया क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

संपादकीय

योजनाएं कई, फिर भी स्कूल छोड़ रहीं बेटियां, 9वीं-10वीं में सबसे ज्यादा ड्रॉपआउट

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल लद्दाख में माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक 15.6 फीसदी दर्ज की गई। शिक्षा किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास का आधार स्तंभ होती है। यह भी जरूरी है कि शिक्षा में अमीर-गरीब, जाति, धर्म, क्षेत्र या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए ताकि सबको सामान अवसर मिल सके। यह सच है कि भारत के शिक्षित समाज में पिछले कुछ दशकों से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है लेकिन चुनौतियां अभी बरकरार हैं।हाल ही में संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, साल 2025-26 में देश भर में नौवीं और दसवीं कक्षा के स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर 8 फीसदी रही जो अन्य कक्षाओं के मुकाबले सबसे अधिक है। यह हाल तब है जब सरकार की ओर से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और समग्र शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम एवं योजनाएं शुरू की गई हैं। सवाल है कि जब सबको शिक्षा के समान और सुलभ अवसर मुहैया कराने की नीतियां लागू की जाती हैं तो लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता बीच रास्ते में ही दम क्यों तोड़ देती है?इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो इसका प्रकाश पूरे परिवार को आलोकित करता है। योग्यता की बात की जाए तो देश में हर साल स्कूली बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियां अव्वल रहती हैं। इसके बावजूद अगर उन्हें किसी कारणवश माध्यमिक स्तर पर ही स्कूल छोड़ने को विवश होना पड़े तो इसे व्यवस्था की नाकामी नहीं तो और क्या कहा जाएगा।सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल लद्दाख में माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक 15.6 फीसदी दर्ज की गई। इसके बाद असम और कर्नाटक का स्थान है जहां यह दर 13.9 फीसदी रही। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं जिनमें लड़कियों का घरेलू कार्यों और आर्थिक मामलों में परिवार का सहयोग करने के लिए स्कूल छोड़ देना या फिर माता-पिता का उनकी आगे की शिक्षा को जरूरी न समझना भी शामिल है। अहम सवाल यही है कि क्या सरकार की ओर से इन कारणों को समझने और उनका समाधान करने का ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा ताकि कोई भी लड़की आर्थिक या पारिवारिक समस्याओं की वजह से शिक्षा से वंचित न रहे? जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए लक्षित आतंकी हमले में दो प्रवासी मजदूरों की मौत ने एक बार फिर यही सवाल उठाया है कि आतंकवाद पर काबू पाने के लिए की जा रही तमाम कवायदों का क्या हासिल है और आज भी अक्सर यह बेलगाम क्यों दिखता है।

पीओके की पुकार और दुनिया की जिम्मेदारी

(ललित गर्ग)

लोकतांत्रिक शासन की सबसे बड़ी कसौटी यह होती है कि वह संकट के समय जनता के साथ किस प्रकार खड़ा रहता है। यदि जनता की शिकायतों का समाधान संवाद से करने के बजाय दमन से किया जाए, तो यह शासन की कमजोरी का प्रमाण होता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों और असंतोष के प्रति जिस प्रकार का रवैया अपनाए जाने के आरोप लगते रहे हैं, वे चिंता पैदा करते हैं। लोकतंत्र का उत्तर हिंसा नहीं, बल्कि संवाद होता है। दुर्भाग्य से जब शासन संवाद छोड़कर शक्ति प्रदर्शन का मार्ग अपनाता है, तब जनता और व्यवस्था के बीच विश्वास की खाई और गहरी हो जाती है।

पाकिस्तान स्वयं को लोकतांत्रिक राष्ट्र कहता है, लेकिन उसके व्यवहार में लोकतंत्र की मूल भावना बार-बार प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव करवा देना नहीं है, बल्कि असहमति का सम्मान करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना और सत्ता की आलोचना को स्वीकार करना भी है।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में इन दिनों जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, वे केवल एक चुनावी प्रक्रिया की कहानी नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र, मानवाधिकार और जनविश्वास के गहरे संकट की दास्तान हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की वास्तविक शक्ति निष्पक्ष चुनाव, नागरिक स्वतंत्रता और शासन की जवाबदेही में निहित होती है, लेकिन जब चुनाव भय, हिंसा, प्रशासनिक दबाव और धांधली के आरोपों से घिर जाएँ, तब लोकतंत्र का स्वरूप विकृत हो जाता है। आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति इसी कठोर वास्तविकता की ओर संकेत करती है। वहाँ के लोगों का आक्रोश केवल चुनावी अनियमितताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही आर्थिक उपेक्षा, राजनीतिक भेदभाव और नागरिक अधिकारों की अनदेखी के विरुद्ध भी है। यही कारण है कि वहाँ का असंतोष अब स्थानीय मुद्दा न रहकर अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बनता जा रहा है। लोकतंत्र केवल मतपेटियों तक सीमित नहीं होता। लोकतंत्र का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के अपनी इच्छा व्यक्त कर सके और उसकी अभिव्यक्ति का सम्मान हो। यदि किसी क्षेत्र में चुनाव पहले से तय परिणामों का माध्यम बन जाएँ, यदि सत्ता का पूरा तंत्र एक दल विशेष के पक्ष में खड़ा दिखाई दे, यदि विरोध की आवाज को बलपूर्वक दबाया जाए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो, तो उसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में समय-समय पर ऐसे आरोप सामने आते रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सत्ता का प्रभाव प्रशासन और चुनावी व्यवस्था पर स्पष्ट दिखाई देता है। यदि जनता के मन में यह विश्वास ही समाप्त हो जाए कि उसका मत परिवर्तन ला सकता है, तो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार ही समाप्त हो जाता है।

पाकिस्तान स्वयं को लोकतांत्रिक राष्ट्र कहता है, लेकिन उसके व्यवहार में लोकतंत्र की मूल भावना बार-बार प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव करवा देना नहीं है, बल्कि असहमति का सम्मान करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना और सत्ता की आलोचना को स्वीकार करना भी है। यदि विरोध करने वालों को राष्ट्रविरोधी या व्यवस्था विरोधी बताकर दबाने का प्रयास किया जाए, यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर दी जाए और यदि प्रशासन जनता के बजाय सत्ता के हितों की रक्षा करता दिखाई दे, तो लोकतांत्रिक मूल्यों की विश्वसनीयता स्वतः समाप्त होने लगती है। पाकिस्तान की यही दोहरी नीति आज उसके लोकतांत्रिक दावों पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक भी है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद वहाँ का सामान्य नागरिक मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। बिजली संकट, महँगाई, बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं की कमी और विकास की धीमी गति ने जनजीवन को अत्यंत कठिन बना दिया है। यह विडंबना है कि जिन नदियों से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी क्षेत्र के लोग लंबे समय तक बिजली कटौती झेलने को विवश हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके संसाधनों का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन उनके विकास के लिए अपेक्षित निवेश नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में जनता के भीतर असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक है।

लोकतांत्रिक शासन की सबसे बड़ी कसौटी यह होती है कि वह संकट के समय जनता के साथ किस प्रकार खड़ा रहता है। यदि जनता की शिकायतों का समाधान संवाद से करने के बजाय दमन से किया जाए, तो यह शासन की कमजोरी का प्रमाण होता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों और असंतोष के प्रति जिस प्रकार का रवैया अपनाए जाने के आरोप लगते रहे हैं, वे चिंता पैदा करते हैं। लोकतंत्र का उत्तर हिंसा नहीं, बल्कि संवाद होता है। दुर्भाग्य से जब शासन संवाद छोड़कर शक्ति प्रदर्शन का मार्ग अपनाता है, तब जनता और व्यवस्था के बीच विश्वास की खाई और गहरी हो जाती है। विश्व समुदाय के सामने भी यह एक गंभीर नैतिक प्रश्न है। यदि लोकतंत्र और मानवाधिकार वास्तव में सार्वभौमिक मूल्य हैं, तो उनका संरक्षण केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और महाशक्तियाँ अनेक अवसरों पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मानवाधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा की बात करती हैं। यदि यही सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उठ रहे प्रश्नों की भी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। मानवाधिकारों का मूल्य भौगोलिक सीमाओं से निर्धारित नहीं होता। जहाँ भी नागरिकों की स्वतंत्रता और सम्मान प्रभावित होता है, वहाँ वैश्विक समुदाय की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दे।

भारत ने हाल की घटनाओं के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति की ओर आकर्षित किया है और वहाँ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा दमन रोकने

की आवश्यकता पर बल दिया है। इस प्रकार की अपील को केवल कूटनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया पर लगातार प्रश्न उठ रहे हों, यदि नागरिक असुरक्षा और अविश्वास के वातावरण में जी रहे हों और यदि उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हों, तो विश्व समुदाय की निष्क्रियता भविष्य के लिए और भी गंभीर संकट उत्पन्न कर सकती है। पाकिस्तान की लोकतांत्रिक नीतियों का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि एक ओर वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लोकतंत्र, न्याय और जनाधिकारों की बात करता है, वहीं दूसरी ओर अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में उन्हीं मूल्यों को व्यवहार में उतारने में विफल दिखाई देता है। लोकतंत्र की विश्वसनीयता केवल भाषणों से नहीं, बल्कि शासन की कार्यशैली से सिद्ध होती है। यदि नागरिक स्वयं को उपेक्षित, असुरक्षित और असहाय महसूस करें, तो लोकतंत्र का दावा खोखला प्रतीत होने लगता है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ सत्ता परिवर्तन की संभावना, स्वतंत्र संस्थाएँ, निष्पक्ष प्रशासन और नागरिकों की गरिमा की रक्षा है। यदि ये तत्व अनुपस्थित हों, तो चुनाव केवल औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाते हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में संपन्न हों। मतदाता बिना किसी भय या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, राजनीतिक दल समान अवसर प्राप्त करें और चुनावी प्रक्रिया पर जनता का विश्वास पुनर्स्थापित हो। यह केवल उस क्षेत्र के लोगों के हित में नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में स्थिरता और शांति के लिए भी आवश्यक है। विश्व की महाशक्तियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल वक्तव्यों से नहीं होती। जहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएँ कमजोर पड़ती हैं, वहाँ समय रहते निष्पक्ष निगरानी, संवाद और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए रचनात्मक प्रयास आवश्यक होते हैं। यदि दुनिया ऐसे मामलों में मौन रहती है, तो लोकतंत्र के सार्वभौमिक मूल्यों की विश्वसनीयता भी कमजोर पड़ती है।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की वर्तमान परिस्थितियाँ दुनिया के लिए एक चेतावनी हैं कि चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं। यदि यह विश्वास टूट जाता है, तो असंतोष, अस्थिरता और संघर्ष की परिस्थितियाँ जन्म लेती हैं। आज आवश्यकता किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन करने की नहीं, बल्कि लोकतंत्र, न्याय, पारदर्शिता और मानवाधिकारों की रक्षा करने की है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को निष्पक्ष दृष्टि से स्थिति का आकलन करते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि वहाँ के नागरिकों को वही अधिकार और सम्मान मिले, जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के नागरिकों का स्वाभाविक अधिकार है। दुनिया की आँखें अब इस ओर खुलनी चाहिए, क्योंकि जहाँ लोकतंत्र कमजोर होता है, वहाँ अंततः पूरी मानवता की नैतिक शक्ति भी कमजोर पड़ती है। लेखक,

भाषा केवल शब्दों का संसार नहीं, किसी समाज की संस्कृति, स्मृतियों और पहचान का आधार है

(मोनिका भाम्भू कलाना)

मनुष्य ने किसी समय ध्वनि संकेतों से स्वयं को अभिव्यक्त करना सीखा होगा, जिससे भाषा बनी होगी। भाषा और मनुष्य के बीच संबंधों के कई सिरे हैं। यह सीधा और इकहरा संबंध नहीं है।

भाषा केवल सामाजिक जुड़ाव और विचारों की अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं होकर मनुष्य की सांस्कृतिक पहचान का अनिवार्य अंग होती है। किसी जन समुदाय की संस्कृति का सर्वाधिक जीवंत और मूर्त रूप उसकी भाषा में ही मिलता है। किसी संस्कृति का अतीत मिथकों के साथ-साथ उसकी भाषा की अवधारणाओं में भी ध्वनित होता है।

भाषा के माध्यम से हम केवल अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते, बल्कि हम उसमें स्वयं को व्यक्त करते हैं। सच यह है कि भाषा के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है। पशु और देवता के बीच मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जो अपना अन्वेषण स्वयं करता है। भाषा उसके इस आत्म-अन्वेषण का औजार है। यह मनुष्य के शरीर का अदृश्य अंग है, दृष्टि है। सच यह है कि भाषा चाहे किसी भी रूप में अभिव्यक्त हो, उसके बिना मनुष्य में कोई आत्मदृष्टि नहीं बन सकती।भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम भर नहीं होती, वह संस्कृति की वाहक होती है। किसी संस्कृति के बिखर जाने पर भी उसका सत्य उसकी भाषा में जीवित रहता है।

मनुष्य के विकास के दौरान प्रत्येक भाषा की विशिष्ट संरचना बनती है, लेकिन एक बार अस्तित्व ग्रहण करके वह मनुष्य की अंतःप्रक्रियाओं को प्रभावित करने लगती है। भाषा केवल किसी समाज के सांसारिक प्रयोजनों को साधने का माध्यम भर नहीं होती, बल्कि समाज के अंदरूनी स्वभाव, उसके संवेदन तंत्र और चरित्र को भी निर्धारित करती है।

प्रत्येक भाषा की अपनी दृष्टि होती है, जिसके सहारे वह दुनिया को देखती-परखती है। भाषा हमारी संस्कृति का, हमारी अस्मिता का महत्त्वपूर्ण अंग है। संस्कृति के जो बिंब, मिथक, रूपक और विशिष्ट प्रतीक होते हैं, वे सब उसकी भाषा से ही उसके साहित्य में स्थान पाते हैं।

भाषाओं के अपने मिथकीय स्रोत उनकी दुनिया और उनकी संरचना को प्रभावित करते हैं। इसलिए एक ही दुनिया में होते हुए भी हर भाषा की अपनी अलग दुनिया होती है और अपना भूगोल होता है।

प्रत्येक भाषा संस्कृति-सापेक्ष होती है। संस्कृति का दर्शन उसकी भाषा से छनकर आता है। इस तरह भाषा, संस्कृति के दर्शन को उजागर करने वाली खिड़की है। यह एक माध्यम मात्र न होकर स्वायत्त शक्ति का एक साधन है।

किसी समाज और संस्कृति की धार्मिक संवेदनाएं, विश्वास, आस्था और मिथकीय चेतना उसकी भाषा में अपने स्मृति-चिह्न छोड़ती हैं। किसी संस्कृति की पहचान उसके यथार्थ तक सीमित न होकर उसके स्वप्नों तक विस्तृत होती है। इसलिए संस्कृति की बुनावट में भाषा का महत्त्वपूर्ण योग रहता है। संस्कृति के स्वप्न उसकी स्मृतियों द्वारा निर्धारित होते हैं।

हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि भाषा के प्रश्न को महज साहित्य-सृजन का प्रश्न मानकर नहीं टाला जा सकता। वह हमारी सांस्कृतिक मनीषा की बुनावट से जुड़ा है। हमारे संस्कार और हमारी स्मृतियां उसी से आकार ग्रहण करती हैं।

आज जब शब्द पर अनेक साधनों से आक्रमण किया जा रहा है, राजनीति, सिनेमा, विज्ञापन और प्रचार द्वारा उसके आत्यंतिक चरित्र को भ्रष्ट किया जा रहा हो, अनेक साधनों और माध्यमों से उसे कुंद किया जा रहा हो, वहां अपनी भाषा के प्रति प्रतिबद्धता केवल साहित्यिक मूल्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक मूल्य भी होनी चाहिए।

अन्य सामाजिक प्रतिबद्धताएं और मूल्य किसी काम के नहीं रहेंगे, अगर हम अपनी भाषा के प्रति संवेदनशील रुख नहीं अपनाएंगे। साहित्यकार अनेक माध्यमों से दूषित हुए शब्द को फिर से सार्थकता प्रदान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भाषा केवल साहित्य और साहित्यकारों के लिए ही नहीं, बल्कि संस्कृति, समाज और स्वयं मनुष्य की अस्मिता के लिए भी बहुत जरूरी होती है।

किसी समाज की संस्कृति जीवित ही नहीं रह सकती, अगर उसकी भाषा मृत हो जाती है। अगर हमारे अतीत का सब कुछ मर-मिट जाए, लेकिन भाषा बची रहे, तब भी एक समाज के सदस्य आपस में संवाद कर सकते हैं। वे अवचेतन रूप में अपने अतीत से जुड़े रहते हैं और अतीत अदृश्य रूप में उनके वर्तमान में प्रवाहित होता रहता है।

किसी देश की संस्कृति ऐतिहासिक झंझावातों द्वारा क्षत-विक्षत भले ही हो जाए, उसका सत्य उसी भाषा में बचा रहता है। इस तरह भाषा भीतर के सत्य और बाहर के यथार्थ के बीच सेतु का काम करती है। आज तकनीक और संचार साधनों के बढ़ने के साथ जिस अनुपात में भाषा को भ्रष्ट करने के साधन बढ़े हैं, शब्द और अर्थ में अंतराल होता जा रहा है।

बिहार- प्रशांत किशोर की जीत के सियासी मायने चौंकाने वाले

(कमलेश पांडे)

दूसरा बड़ा संदेश यह कि, जनसुराज पार्टी की नई जीत जहाँ भाजपा नीत एनडीए के लिए इस अकल्पनीय पराजय के बाद संगठन और रणनीति की समीक्षा का गहरा अवसर पैदा करता है। वाकई प्रशांत किशोर की जीत भाजपा के लिए स्पष्ट चेतावनी भी है, क्योंकि बांकीपुर जैसी भाजपा की पारंपरिक सीट का उसके हाथ से एक झटके में निकल जाने से यह साफ संकेत मिलता है कि चुनाव जीतने के लिए केवल संगठनात्मक मजबूती ही पर्याप्त नहीं है; बल्कि स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार, सामाजिक समीकरण और मतदाता की अपेक्षाएं भी निर्णायक हो सकते हैं।

बांकीपुर उपचुनाव का सबसे बड़ा संदेश यह है कि, बिहार की राजनीति अब केवल एनडीए बनाम महागठबंधन की दोध्रुवीय प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि जन सुराज ने स्वयं को एक संभावित तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक व मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार को लगभग 19 हजार वोटों से तगड़ी शिकस्त देकर न केवल चुनाव जीता, बल्कि राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया। प्रशांत किशोर की यह जीत केवल एक सीट की जीत नहीं मानी जा रही, बल्कि बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखी जा रही है। ऐसा इसलिए कि प्रशांत किशोर ने भाजपा के तीन दशक से अधिक पुराने गढ़ में अकल्पनीय जीत दर्ज की है और अपनी जन सुराज पार्टी को पहली बड़ी चुनावी सफलता दिलाई है। हालांकि, एक उपचुनाव के परिणाम के आधार पर पूरे राज्य के चुनाव के जनादेश का संकेत मान लेना एक बड़ी सियासी गलतफहमी होगी। फिर भी, उनकी यह जीत कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 18,953 वोटों के भारी अंतर से हराया है। लिहाजा, बांकीपुर उपचुनाव का सबसे बड़ा संदेश यह है कि, बिहार की राजनीति अब केवल एनडीए बनाम महागठबंधन की दोध्रुवीय प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि जन सुराज ने स्वयं को एक संभावित तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। दूसरा बड़ा संदेश यह कि, जनसुराज पार्टी की नई जीत जहाँ भाजपा नीत एनडीए के लिए इस अकल्पनीय पराजय के बाद संगठन और रणनीति की समीक्षा का गहरा अवसर पैदा करता है। वाकई प्रशांत किशोर की जीत भाजपा के लिए स्पष्ट चेतावनी भी है, क्योंकि बांकीपुर जैसी भाजपा की पारंपरिक सीट का उसके हाथ से एक झटके में निकल जाने से यह साफ संकेत मिलता है कि चुनाव जीतने के लिए केवल संगठनात्मक मजबूती ही पर्याप्त नहीं है; बल्कि स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार, सामाजिक समीकरण और मतदाता की अपेक्षाएं भी निर्णायक हो सकते हैं। तीसरा बड़ा संदेश यह कि, इस अकल्पनीय जीत से जन सुराज पार्टी को राजनीतिक वैधता मिली है। अब जन सुराज को केवल एक अभियान नहीं, बल्कि चुनाव जीतने में सक्षम राजनीतिक दल के रूप में देखा जाएगा। वाकई जिस चुनौती भरे सियासी परिदृश्य में प्रशांत किशोर ने अपनी जीत का परचम लहराया है और भाजपा के लंबे समय से सुरक्षित माने जाने वाले बांकीपुर के गढ़ में 30 साल बाद ही सही, पर सेंध लगा डाली है; वह नवोदित पार्टी के लिए एक अहम उपलब्धि है। इससे भाजपा का मनोबल टूटने के पुष्ट संकेत मिले हैं। चौथा बड़ा संदेश यह कि, जन सुराज पार्टी की पहली चुनावी जीत का सेहरा खुद पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के सिर पर ही बंधा है और वो अपना पहला चुनाव लड़कर ही विधायक बनकर विधान सभा पहुंच चुके हैं, जिससे बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा करने के उनके मिशन को काफी बल मिला है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर की नई भूमिका की चर्चा अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि चुनावी रणनीतिकार से विधायक बनने के बाद उन्हें विधानसभा के भीतर अपनी राजनीति और वैकल्पिक नीतियों को सीधे प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। पांचवां बड़ा संदेश यह कि, जहाँ तक 2026 में हुए बांकीपुर बिहार विधानसभा उप चुनाव के मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात है तो यह परिणाम जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगा और आगामी चुनावों में उम्मीदवारों व समर्थकों को आकर्षित कर सकता है। चूंकि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनावों में शुरुआती धमाल मचाने के बाद प्रशांत किशोर की रणछोड़ रणनीतिकार और बुजदिल राजनेता वाली जो छवि बनी थी, अब उससे उन्हें मुक्ति मिली है और वह एक जुझारू राजनेता के रूप में उभरे हैं। छठा बड़ा संदेश यह कि, जन सुराज पार्टी और प्रशांत किशोर के इस सियासी उभार से एक नई युवा और शहरी राजनीति के संकेत मिले हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार में रोजगार, शिक्षा और सुशासन जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। इस प्रकार यदि यह रुझान अन्य क्षेत्रों में भी दिखता है, तो इससे बिहार की चुनावी राजनीति में मुद्दा-आधारित प्रतिस्पर्धा और मजबूत हो सकती है। सातवां बड़ा संदेश यह कि, विपक्षी राजनीति भी अब एक नई करवट लेगी। उसे एक नया सकारात्मक विकल्प मिलेगा। बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरह से राजद नीत महागठबंधन का वोट बैंक जनसुराज की ओर यकायक शिफ्ट हुआ, यह उसके समक्ष भी अपने जनाधार को मजबूत बनाए रखने की एक तगड़ी चुनौती समुपस्थित करता है। इससे राजद और महागठबंधन के सामने भी अब एक नई चुनौती खड़ी होगी, क्योंकि यदि जन सुराज पार्टी आगे भी विपक्षी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इससे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के लिए विपक्ष का निर्विवाद केंद्र बने रहना कठिन हो सकता है। ऐसा इसलिए भी कि बांकीपुर में राजद तीसरे स्थान पर रही। आठवां बड़ा संदेश यह कि, बिहार जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रांत में भाजपा की यह पराजय उसके नेताओं की आपसी रस्साकशी का निराशाजनक परिणाम तो है ही, लेकिन उलजुलूल समीकरणों को साधने की उसकी राजनीतिक फितरत, और इसके चक्कर में बिगड़ैल बोलों पर बरती गई रणनीतिक खामोशी का यह साइड इफ़ेक्ट्स भी समझा जा सकता है। यह घटनाक्रम पुनः भाजपा को खुली नसीहत देता है कि यदि बनावटी ओबीसी राजनीति के चक्कर में वह अपनी मूल राजनीतिक सवर्ण सियासी पूंजी भी न गंवा बैठे, जो कि कांग्रेस की ऐसी ही क्षुद्र सियासत से आजिज आकर भाजपा की ओर 1990 के दशक में शिफ्ट हुआ था, और अब विकल्प मिलते ही भाजपा की क्षुद्र सियासी चाल को भी नया राजनीतिक पाठ पढ़ाने पर आमादा दिखता है। नवां बड़ा संदेश यह कि, बिहार में सत्ता मिलते ही नवभाजपाइयों यानी राजद से भाजपा में आए नागमणि जैसे सामाजिक विषधर नेताओं ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को धत्ता बताकर बैकवर्ड-फॉरवर्ड की जो लोहियावादी सियासत परवान चढ़ानी चाही, उसका साइड इफेक्ट्स भी । बांकीपुर उपचुनाव में दिखा है। क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर को जातिवादी नजरिए से देखना और वैसी ही गोलबंदी को परोक्ष शह देकर बैकफुट पर लौटने से सवर्णों के बीच गलत संदेश गया है। इसलिए भाजपा के ओबीसी-दलित नेताओं को धुर सवर्ण विरोधी मानसिकता से बचना होगा, अन्यथा प्रतिक्रिया वश सवर्ण यदि ओबीसी की राजद और दलितों की लोजपा रामविलास को सियासी शह दे देंगे तो भाजपा के ओबीसी-दलित नेता न घर के रहेंगे, न घाट के। दसवां बड़ा राजनीतिक संदेश और स्वाभाविक सवाल यह है कि भाजपा के पैराशूट राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा खाली की गई इस प्रतिष्ठित सीट पर बीजेपी चुनाव कैसे और क्यों हारी? क्या इसके पीछे भी उसकी कोई बड़ी रणनीति है या फिर अपने बड़े नेताओं के खिलाफ हुई भितरघात की वजह से भाजपा को यह शर्मनाक पराजय झेलनी पड़ी। चूंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी सत्ताधारी पार्टी प्रायः उपचुनाव नहीं हारती है, इसलिए यदि भाजपा हारी है तो इससे भी कई बड़े सवाल उपजते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या बांकीपुर में हुई चुनावी हार भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार की हार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्वमुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और बड़बोले केंद्रीय मंत्री गण चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की संयुक्त हार है, क्योंकि सबने एक दूसरे के साथ सियासी घात-प्रतिघात किया है, ताकि सूबाई राजनीति में गठबंधन साथियों की प्रासंगिकता बनी रहे।

आयुक्त वीबी -जी रामजी ने किया ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण, पीएम आवास के हितग्राहियों को सौंपी खुशियों की चाबी

आवास निर्माण,जल सुरक्षा एवं ग्रामीण अधोसंरचना गुणवत्ता पर विशेष जोर

बलौदाबाजार-भाटापारा/मूक पत्रिका

ताराचंद कठोत्रे / आयुक्त व्हीबी -जी रामजी एवं संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तारण प्रकाश सिन्हा शुक्रवार को बलौदाबाजार पहुंचे।इस दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। आयुक्त ने जनपद पंचायत बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम पंचायत बेमेतरा तथा जनपद पंचायत पलारी अंतर्गत ग्राम पंचायत सितदेवरी में विभिन्न विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण करते हुए हितग्राहियों एवं ग्रामीणों से सीधे संवाद किया।निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत निर्मित आवासों का अवलोकन किया तथा आवास पूर्ण कर चुके हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से खुशियों की चाबी प्रदान की। हितग्राहियों से आवास निर्माण, प्राप्त सहायता, निर्माण की गुणवत्ता एवं योजना से उनके जीवन में आए बदलाव के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र परिवारों को योजना का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें । आयुक्त ने व्हीबी- रामजी अंतर्गत जल सुरक्षा श्रेणी में निर्मित एवं प्रगतिरत कार्यों का भी विस्तृत निरीक्षण किया।इस दौरान नवीन तालाब, अमृत सरोवर, सैंड फिल्टर आधारित बोरवेल रिचार्ज संरचना तथा चेक डैम निर्माण कार्यों की स्थल पर तकनीकी एवं उपयोगिता संबंधी समीक्षा की । उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल संरक्षण एवं भू-जल पुनर्भरण से जुड़े कार्य केवल निर्माण तक सीमित न रहें, बल्कि उनका चयन स्थानीय आवश्यकता, कैचमेंट, जलधारण क्षमता एवं दीर्घकालिक उपयोगिता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि व्हीबी-जी रामजी का उद्देश्य रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्राम पंचायतों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण, जल सुरक्षा को सुदृढ़ करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाना है। अतः योजना अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक कार्य का प्रत्यक्ष लाभ ग्रामीण समुदाय को दिखाई देना चाहिए।स्थल निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर सहज एवं आत्मीय वातावरण में चर्चा की तथा योजनाओं के क्रियान्वयन, स्थानीय आवश्यकताओं, रोजगार, आवास एवं विकास कार्यों के संबंध में उनके अनुभव और सुझाव सुने। उन्होंने मैदानी अमले को निर्देशित किया कि ग्रामीणों की वास्तविक आवश्यकताओं को समझते हुए ग्राम सभा से अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप प्राथमिकता आधारित कार्य संपादित किए जाएं। इसके पश्चात जिला पंचायत सभाकक्ष बलौदाबाजार में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक मे व्हीबी-जी रामजी एवं पीएम आवास योजना ग्रामीण सहित ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। आयुक्त ने योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्ध पूर्णता, श्रमिक नियोजन, तकनीकी मापदंडों के पालन तथा पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फील्ड निरीक्षण को नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाया जाए तथा प्रत्येक निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न किया जाए। जल संरक्षण संरचनाओं के माध्यम से अधिकतम वर्षाजल संचयन, भू-जल स्तर में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी जल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में परिणामोन्मुखी कार्य करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण एवं समीक्षा के दौरान सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल एवं संबंधित जनपद पंचायतों के अधिकारी-कर्मचारी, तकनीकी अमला, पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कांकेर शहर की बैठक संपन्न, स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली के खिलाफ15 अगस्त के बाद घर-घर चलाया जाएगा जनजागरण अभियान

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर: कांकेर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई। बैठक में संगठन को वार्ड एवं बूथ स्तर पर मजबूत करने, मंडल पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करने तथा प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बूथ एवं वार्ड कमेटियों के गठन के पश्चात मंडल पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए प्रत्येक वार्ड में माह में कम से कम एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इन बैठकों के माध्यम से संगठनात्मक गतिविधियों की नियमित समीक्षा करने तथा स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाने पर जोर दिया गया।

बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से स्मार्ट मीटर एवं महंगे बिजली बिल के संबंध में प्राप्त दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दी गई। निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त के बाद शहर के प्रत्येक वार्ड में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर पहुंचकर बिजली उपभोक्ताओं से संपर्क करेंगे तथा स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिल से संबंधित निर्धारित फार्म भरवाकर उनका संकलन करेंगे।

संकलित फार्म संगठन के माध्यम से जिला कांग्रेस कमेटी को सौंपे जाएंगे। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में राज्यपाल के समक्ष महंगी बिजली का विरोध दर्ज कराते हुए स्मार्ट मीटर बदलने की मांग रखी जाएगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए शहर अध्यक्ष श्री यासीन करानी ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए नए कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की विफलताओं एवं आम जनता से जुड़े मुद्दों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए शहर में व्यापक मुहिम चलाई जाएगी। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भी संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों को लेकर अपने-अपने सुझाव रखे। बैठक में वार्ड स्तर पर सक्रियता बढ़ाने, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा जनहित के मुद्दों पर मजबूती से आवाज उठाने का संकल्प लिया गया।

दर्रामुड़ा में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था बदहाल, खराब लाइटें रिपेयरिंग के नाम पर उतारी गईं

30 नग स्ट्रीट लाइट की ?45 हजार में हुई थी खरीदी, रात में अंधेरे से ग्रामीण परेशान

खरसिया/मूक पत्रिका

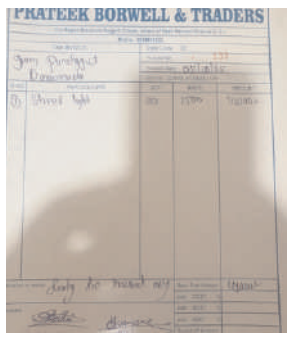

जनपद पंचायत खरसिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत दर्रामुड़ा में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रतीक बोरवेल एंड ट्रेडर्स से करीब 30 नग स्ट्रीट लाइट ?45 हजार की लागत से खरीदी गई थीं।

बताया जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट खराब होने के बाद पंचायत द्वारा उन्हें खंभों से निकालकर रिपेयरिंग के नाम पर ले जाया गया, लेकिन मरम्मत के बाद भी अब तक कई स्ट्रीट लाइटों को दोबारा खंभों पर नहीं लगाया गया है। इसके चलते रात के समय गांव के कई हिस्सों में अंधेरा छाया रहता है।ग्रामीणों का कहना है कि स्ट्रीट लाइटों के बंद रहने से रात में आने-जाने में परेशानी होती है। खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को अंधेरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों ने पंचायत से खराब स्ट्रीट लाइटों को जल्द से जल्द ठीक कर पुनः लगाने की मांग की है।

पंचायत की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल-ग्रामीणों ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब पंचायत द्वारा जनता के पैसे से स्ट्रीट लाइट खरीदी गई थी, तो खराब होने के बाद उन्हें रिपेयरिंग के नाम पर उतारकर लंबे समय तक क्यों रखा गया है? वहीं, 30 नग स्ट्रीट लाइट की खरीदी और उनके रखरखाव पर खर्च की गई राशि का उपयोग किस प्रकार हुआ, इसकी भी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है।

ग्रामीणों ने जनपद पंचायत खरसिया के अधिकारियों से मामले की जांच कर स्ट्रीट लाइट व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है, ताकि रात के समय ग्रामीणों को अंधेरे की समस्या से निजात मिल

एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश

बलदाकछार में परिक्षेत्र स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन

बलौदाबाजार/मूक पत्रिका

ताराचंद कठोत्रे / वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार धम्मशील गणवीर के निर्देशानुसार वन परिक्षेत्र बल्दाकछार में गुरुवार को परिक्षेत्र स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक पेड माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का सन्देश दिया गया। इस अवसर पर वनमण्डलाधिकारी धम्मशील गणवीर ने कहा कि ÷एक पेड़ माँ के नाम÷ अभियान केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता विकसित करने का एक जनआंदोलन है। उन्होंने सभी नागरिकों से अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने तथा लगाए गए पौधों को वृक्ष बनने तक संरक्षित रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, वन प्रबंधन समितियों, विद्यार्थियों एवं स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता से ही पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण में वृद्धि, जलवायु संतुलन एवं प्रकृति संरक्षण में जनभागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों को बताया गया कि वृक्षारोपण के साथ-साथ पौधों का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। वन महोत्सव के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रकृति संरक्षण के इस अभियान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान ग्राम अर्जुनी (ब) स्थित गौठान में ÷एक पेड़ माँ के नाम÷ अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानीय एवं उपयोगी प्रजातियों के पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों, वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों, विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने तथा लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया गया। सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के निर्माण के लिए सक्रिय सहभागिता का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी बलौदाबाजारसुश्री एकता कर सहित वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही बलदाकछार वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले जनपद सदस्य, सरपंचगण, वन प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी एवं ग्रामीणजन कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक शामिल हुए।

वित्तीय साक्षरता लैब में विद्यार्थियों ने सीखे बचत, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान के गुर

शैक्षणिक भ्रमण से विद्यार्थियों को मिली वित्तीय प्रबंधन की व्यवहारिक सीख

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/ :- कांकेर 7 अगस्त 2026 विद्यार्थियों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने तथा बैंकिंग, बचत, निवेश, बीमा एवं डिजिटल भुगतान के प्रति जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला वित्तीय साक्षरता लैब, कांकेर में हायर सेकेंडरी विद्यालयों के विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर तथा जिला पंचायत सीईओ हरेश मंडावी के निर्देशन में, जिला शिक्षा अधिकारी रमेश कुमार निषाद एवं डीएमसी नवनीत पटेल के मार्गदर्शन में आयोजित इस भ्रमण में हायर सेकेंडरी स्कूल आतुरगांव, सेजेस हायर सेकेंडरी स्कूल पटौद तथा शहीद रामकुमार यादव कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, कांकेर के विद्यार्थियों ने सहभागिता की। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने वित्तीय साक्षरता लैब में स्थापित विभिन्न शिक्षण मॉडल, डिजिटल प्रस्तुतीकरण एवं इंटरैक्टिव गतिविधियों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली, धन प्रबंधन और डिजिटल वित्तीय सेवाओं की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त की। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को नियमित बचत की आदत विकसित करने, बैंकिंग सेवाओं का सुरक्षित उपयोग करने, बीमा एवं निवेश के महत्व तथा डिजिटल भुगतान प्रणाली के लाभों के बारे में सरल एवं रोचक ढंग से जानकारी दी।विशेषज्ञों ने बताया कि वर्तमान समय में वित्तीय साक्षरता प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक है। सही वित्तीय निर्णय न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि भविष्य को भी मजबूत बनाते हैं। विद्यार्थियों को ऑनलाइन लेन-देन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, साइबर ठगी से बचाव, मजबूत पासवर्ड के उपयोग, ओटीपी साझा नहीं करने तथा सुरक्षित डिजिटल भुगतान के उपायों से भी अवगत कराया गया।कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने विशेषज्ञों से कई प्रश्न पूछे, जिनका विस्तारपूर्वक समाधान किया गया। डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम, बीमा योजनाओं एवं निवेश के विभिन्न विकल्पों के संबंध में विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 24 IFS अधिकारियों के तबादले, सारंगढ़-बिलाईगढ़ के ष्ठस्नह्व विपुल अग्रवाल भी बदले..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

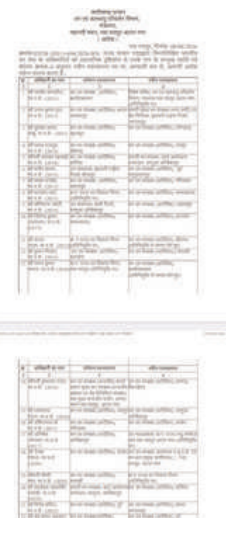

छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। शासन ने 24 भारतीय वन सेवा (ढ्ढस्नस्) अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना का आदेश जारी किया है। इस फेरबदल में प्रदेश के कई वन मंडलों के वन मंडलाधिकारी (ष्ठस्नह्व) भी बदले गए हैं। इसका असर सारंगढ़-बिलाईगढ़ वन मंडल पर भी पड़ा है।

विपुल अग्रवाल का सूरजपुर तबादला-जारी आदेश के अनुसार सारंगढ़-बिलाईगढ़ के वन उप संरक्षक (प्रादेशिक) विपुल अग्रवाल का तबादला कर उन्हें सूरजपुर वन मंडल में वन उप संरक्षक (प्रादेशिक) की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विपुल अग्रवाल के स्थान पर पुष्पलता टंडन को सारंगढ़-बिलाईगढ़ का नया वन उप संरक्षक (प्रादेशिक) नियुक्त किया गया है। पुष्पलता टंडन वर्ष 2016 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं।

जिले में वन विभाग की कमान अब पुष्पलता टंडन के हाथों-नई पदस्थापना के बाद अब सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में वन विभाग से जुड़े प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी पुष्पलता टंडन संभालेंगी। उनके सामने जिले में वन संरक्षण, अवैध कटाई पर नियंत्रण, वन क्षेत्र से जुड़े मामलों और विभागीय योजनाओं के बेहतर संचालन की जिम्मेदारी होगी।

24 अधिकारियों की बदली पदस्थापना-वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से जारी आदेश में प्रदेश के कुल 24 ढ्ढस्नस् अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। इनमें कई अधिकारियों को अलग-अलग वन मंडलों में ष्ठस्नह्व की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को अन्य विभागीय पदों पर पदस्थ किया गया है। शासन के आदेश में प्रशासनिक दृष्टिकोण से अधिकारियों की नई पदस्थापना किए जाने की बात कही गई है। आदेश 8 अगस्त 2026 को जारी हुआ है और इसमें किए गए स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। सारंगढ़-बिलाईगढ़ में ष्ठस्नह्व के बदलाव को जिले के वन विभाग के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है।

शिशु को 6 महीने तक केवल स्तनपान कराएं

महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्यक्रम आयोजन कर दी स्तनपान ज्ञान

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सारंगढ़ के आशा निकेतन वृद्धा आश्रम में स्तनपान से जुड़ा कार्यक्रम किया। इस आयोजन में महिला एवं बाल विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी, सेक्टर सुपरवाइजर और सुपरवाइजर सहित कई महिलाएं उपस्थित थीं। प्रशिक्षक और वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से स्तनपान सिखाया गया और इस ज्ञान को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से शिशुवती महिलाओं को समझाने के निर्देश महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने दिए।

कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि, स्तनपान सबसे प्राकृतिक चीजों में से एक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह माताओं और उनके शिशुओं दोनों के लिए स्वाभाविक रूप से होता है। इसमें समय और अभ्यास लगता है। और हर माँ की स्तनपान की कहानी अलग होती है, लेकिन इन सभी कहानियों में एक बात समान है, वे अपने बच्चों को जीवन की सबसे स्वस्थ शुरुआत दे रहे हैं। स्तनपान शिशुओं को वह पोषण, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है जिसकी उन्हें मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान बनने के लिए आवश्यकता होती है। स्तनपान कराने वाली माताओं को अपने साथी, परिवार, स्वास्थ्यकर्मियों, नियोक्ताओं और पूरे समुदाय के सहयोग की आवश्यकता होती है।

जन्म के पहले घंटे में स्तनपान कराएं

चाहे आप स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल या घर पर बच्चे को जन्म दें, जन्म के पहले घंटे के भीतर नवजात शिशु को स्तनपान कराने से स्तनपान सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ घंटों की देरी भी स्तनपान को सफलतापूर्वक शुरू करने में मुश्किल पैदा कर सकती है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद (और उससे ठीक पहले भी) आपका शरीर शिशु का ÷पहला दूध÷ बनाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। यह गाढ़ा, अक्सर सुनहरे रंग का होता है और कम मात्रा में निकलता है, लेकिन शक्तिशाली एंटीबॉडी से भरपूर होता है, और नवजात शिशु को शुरुआती घंटों और दिनों में ठीक यही चाहिए होता है, जब उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली अभी विकसित हो रही होती है। मां का दूध पहले टीके की तरह काम करता है, जो आपके शिशु को हानिकारक बीमारियों से बचाने में मदद करता है। नवजात शिशुओं में दूध पीने की सहज प्रवृत्ति होती है और वे आमतौर पर स्तनपान सीखने के लिए तैयार होते हैं। जन्म के तुरंत बाद शिशु को त्वचा से त्वचा मिलाकर गोद में लेने से आपका शिशु के साथ गहरा जुड़ाव बनता है, शिशु गर्म रहता है और आपकी त्वचा से अच्छे बैक्टीरिया शिशु तक पहुंचते हैं, जो उसकी विकसित हो रही प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। शुरुआती स्तनपान और त्वचा से त्वचा मिलाकर गोद में लेने से शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और स्तनपान की शुरुआत आसान हो जाती है। अगर कोई माता तुरंत स्तनपान नहीं करा पा रही हैं, तो निराश न हों। जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। बार-बार बच्चे को स्तनपान कराने और त्वचा से त्वचा का संपर्क बनाए रखने से समय के साथ स्तनपान शुरू करने में मदद मिलेगी।कुछ दिनों बाद (अक्सर तीसरे-चौथे दिन के आसपास), आपका दूध आना शुरू हो जाता है और आपके स्तन भरे हुए, भारी और असहज महसूस होने लगते हैं। यह आपके शरीर के सामान्य समायोजन का एक हिस्सा है, लेकिन कभी-कभी यह दर्दनाक और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि आपको इस समय कठिनाई हो रही है या आप चिंतित या परेशान महसूस कर रही हैं, तो मदद लें। यदि आपको स्तनपान कराने में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो किसी योग्य स्वास्थ्यकर्मी या किसी भरोसेमंद मित्र या परिवार के सदस्य, जैसे कि आपकी माँ या सास से बात करें।

जन्म के पहले घंटे से लेकर 6 महीने की उम्र तक, आपका शिशु आपके दूध से ही सभी आवश्यक पोषण प्राप्त कर सकता है। इस दौरान उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं होती ङ्क न ही किसी अन्य खाद्य पदार्थ या तरल पदार्थ की, यहां तक ??कि पानी की भी नहीं। अपने शिशु के 6 महीने का होने से पहले स्तनपान के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ या तरल पदार्थ देना, दस्त जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है, जिससे आपका बच्चा पतला और कमजोर हो सकता है, और यह जानलेवा भी हो सकता है। माता-पिता और देखभाल करने वाले 6 महीने की उम्र से स्तनपान के अलावा नरम खाद्य पदार्थ देना शुरू कर सकते हैं और उन्हें 2 साल या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखना चाहिए। स्तनपान आपके शिशु को कान के संक्रमण, दस्त, निमोनिया और अन्य बचपन की बीमारियों से बचाता है। स्तनपान न केवल आपके शिशु के लिए अच्छा है, बल्कि माताओं के लिए भी अच्छा है! स्तनपान कराने वाली महिलाओं में स्तन और अंडाशय के कैंसर का खतरा भी कम होता है। यदि आप स्तनपान कराने में असमर्थ हैं, तो कोई बात नहीं। अपने और अपने बच्चे के लिए सर्वोत्तम विकल्पों पर चर्चा करने के लिए अपने स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी से परामर्श लें। सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा ठीक से जुड़ा हुआ है। सही तरह से जुड़ाव स्थापित करना यह सुनिश्चित करने की कुंजी है कि स्तनपान आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए एक आरामदायक अनुभव हो। अगर आपके निप्पल में दर्द हो या वे फट जाएं, तो आमतौर पर यह इस बात का संकेत है कि दूध पिलाते समय आपका बच्चा स्तन से ठीक से नहीं चिपक रहा है। अगर आपके एक या दोनों निप्पल फटने लगें या उनसे खून आने लगे, तो जितनी जल्दी हो सके अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। दर्द से राहत पाने के लिए, दूध पिलाने के बाद थोड़ा सा स्तन का दूध उन पर लगाएं। स्तन के दूध में उपचार गुण होते हैं। प्रसव के बाद, किसी कुशल स्वास्थ्यकर्मी से स्तनपान संबंधी सहायता लें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके बच्चे का स्तनपान से अच्छा जुड़ाव हो और वह सफलतापूर्वक दूध पी सके। शिशु के मुंह के ऊपर की ओर निप्पल के आसपास का हिस्सा नीचे की ओर की तुलना में अधिक दिखाई देता है। आपके शिशु का मुंह चौड़ा खुला हुआ है।

भालूनारा से रॉबर्टसन तक जर्जर सड़क को लेकर फिर होगा अनिश्चितकालीन चक्काजाम

वादे पूरे नहीं होने पर ग्रामीणों का बड़ा आंदोलन, 16 अगस्त 2026 से शुरू होगा धरना प्रदर्शन

खरसिया/मूक पत्रिका

भालूनारा से रॉबर्टसन रेलवे साइडिंग तक लंबे समय से जर्जर पड़ी सड़क की समस्या को लेकर एक बार फिर ग्रामीणों ने आंदोलन का ऐलान किया है। पूर्व में सड़क निर्माण को लेकर किए गए आश्वासनों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि भालूनारा चौक से नवागांव, पामगढ़ चौक, छोटेडूमरपाली, बड़ेडूमरपाली एवं अंबेडकरनगर होते हुए रॉबर्टसन रेलवे साइडिंग तक सड़क की हालत बेहद खराब है। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और जर्जर स्थिति बनी हुई है, जिससे राहगीरों एवं आसपास के ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

16 अगस्त से अनिश्चितकालीन चक्काजाम–जर्जर सड़क की समस्या और पूर्व में किए गए वादे पूरे नहीं होने के विरोध में ग्रामीणों ने अब 16 अगस्त 2026 से अनिश्चितकालीन चक्काजाम धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। दिनांकः 16 अगस्त 2026 से स्थानः नवागांव, यस किराना स्टोर्स के सामने आंदोलनः अनिश्चितकालीन चक्काजाम एवं धरना प्रदर्शनग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि जब तक सड़क की समस्या का स्थायी समाधान और सड़क निर्माण को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वादे पूरे नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी ग्रामीणों का कहना है कि सड़क को लेकर पहले भी आश्वासन दिए गए थे, लेकिन समय बीतने के बाद भी सड़क की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। अब ग्रामीणों ने अपने हक और सड़क की स्थायी समस्या के समाधान के लिए दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाया है। आंदोलन को लेकर प्रभावित गांवों के ग्रामीणों में तैयारी शुरू हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि 16 अगस्त से शुरू होने वाला यह आंदोलन अनिश्चितकालीन रहेगा।

काम दिलाने के नाम पर महिला की खरीद-फरोख्त: 50 हजार में बेचकर कराई जबरन शादी, 3 आरोपी गिरफ्तार

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/ उत्तर बस्तर कांकेर जिले की बांदे थाना पुलिस ने मानव तस्करी और महिला उत्पीड़न के एक गंभीर मामले का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक शादीशुदा महिला को मुंबई में काम दिलाने का झांसा देकर मध्यप्रदेश ले जाकर 50,000 रुपये में बेच दिया और उसकी जबरन शादी करा दी। पुलिस ने महिला को मध्यप्रदेश के खंडवा जिले से सुरक्षित बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बांदे थाना क्षेत्र की एक महिला 20 मार्च 2026 को बिना बताए घर से लापता हो गई थी। महिला के पति की रिपोर्ट पर बांदे पुलिस ने 09 अप्रैल 2026 को गुम इंसान कायम कर तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि गुमशुदा महिला मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुर्रे के मार्गदर्शन और एसडीओपी कुलदीप बंजारे के पर्यवेक्षण में एक विशेष पुलिस टीम गठित कर खंडवा रवाना की गई।5 अगस्त 2026 को पुलिस टीम ने खंडवा पहुंचकर महिला को जितेंद्र राठौर नामक व्यक्ति के कब्जे से सुरक्षित बरामद किया। 5 माह तक बंधक बनाकर रखा बरामदगी के बाद महिला ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि अनिता पवार (निवासी बेलगाल) और जमना लाल भील (निवासी खंडवा) ने उसे मुंबई में रोजगार दिलाने का लालच देकर बहलाया-फुसलाया और मध्यप्रदेश ले गए। वहां उसे 50,000 रुपये में जितेंद्र राठौर के हाथों बेच दिया गया। जितेंद्र ने महिला से जबरन शादी की और पिछले 5 महीनों से उसे अपने घर में जबरदस्ती पत्नी बनाकर रखा था।पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी पीड़िता के बयान और मामले की गंभीरता को देखते हुए बांदे पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफभारतीय न्याय संहिता (ब्हृस्) की धारा 143(2), 61(2), 127 (4) और 87 के तहत अपराध क्रमांक 62/2026 दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपि अनिता पवार (उम्र 40 वर्ष), पति जगत पवार, निवासी बेलगाल, थाना बांदे, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.),जितेंद्र राठौर (उम्र 30 वर्ष), पिता उत्तम राठौर, निवासी आरूद, थाना पंधाना, जिला खंडवा (म.प्र.), जमना लाल भील (उम्र 41 वर्ष), पिता चिताराम भील, निवासी आव लिया, थाना छैगांव माखन, जिला खंडवा (म.प्र.) इस कार्रवाई में बांदे थाना प्रभारी निरीक्षक रामचंद्र साहू, सउनि देवनारायण बंजारे, प्रधान आरक्षक सूर्यदेव कुंजाम, तुलाराम, प्रशांत दास, आरक्षक यशवंत मंडावी, अमृत नेताम, मोहन दुग्गा, अश्वनी कुंजाम, प्यारेलाल तारम, महिला आरक्षक संतोषी मातलाम, हिरोंदा दुग्गा, जया सलाम और गोपनीय सैनिक अंजली पाल की विशेष भूमिका रही।

श्री शिव महापुराण कथा में : पार्थिव शिव पूजन और महिमा से निहाल हुए श्रद्धालु

बेमेतरा। नगर के राम मंदिर प्रांगण में अत्यंत श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ दिव्य शिव महापुराण कथा के तृतीय दिवस कथा व्यास पूज्य संत गणेश्वर शास्त्री महाराज ने शिव महापुराण के महात्म्य का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन करते हुए उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। पूज्य शास्त्री जी ने बताया कि कलयुग में भगवान शिव की महिमा और कथा का श्रवण ही मानव जीवन के उद्धार का सबसे सुगम माध्यम है। कथा के इस आयोजन से न केवल जीवित मनुष्यों का जीवन धन्य होता है, बल्कि उनके पितरों को भी परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए व्यास जी ने देवराज नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी चंचुला के उद्धार की कथा सुनाकर सभी को भावविभोर कर दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान शिव की असीम कृपा से चंचुला ने अपने पति की दुर्दशा को सुधारकर उसे परम धाम पहुंचाया। इसके साथ ही कथा में प्रथम ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव तथा भगवान ब्रह्मा एवं हरि विष्णु के दिव्य चरित्र का विस्तृत वर्णन किया गया। महाराज जी ने कहा कि जल में डूबकर, अग्नि में जलकर अथवा दुर्घटना में असमय मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों की मुक्ति केवल शिव महापुराण या श्रीमद्भागवत के आयोजन से ही संभव है। व्यास जी ने शिव के सकल एवं निष्कल रूप तथा पूजन-संकीर्तन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। शिवलिंग निर्माण और उसकी महिमा बताते हुए शास्त्री जी ने कहा कि सतयुग में मणिलिंग, त्रेता में स्वर्ण लिंग, द्वापर में पारद लिंग और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का विशेष महात्म्य है। विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु शिवलिंगों की संख्या निर्धारित है; जैसे विद्या प्राप्ति के लिए 1,000, धन व पुत्र प्राप्ति के लिए 500-500 तथा मोक्ष हेतु एक करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने का विधान है। इसके साथ ही, बाणलिंग, सिद्धलिंग एवं स्वयंभू लिंग में चंड का अधिकार न होने से इनका प्रसाद ग्रहण करना निष्पाप बनाता है। शिवलिंग को स्नान कराकर उस जल का तीन बार आचमन करने मात्र से मनुष्य के समस्त पापों का तत्काल शमन हो जाता है। आयोजन में आचार्य पंडित द्वारका प्रसाद शास्त्री, आचार्य गोरेलाल पाठक, आचार्य उमाशंकर शर्मा एवं आचार्य राजेश्वर शुक्ला जी मुख्य आचार्यत्व संभाल रहे हैं।

वर्ष 2023 के 3 नये कानून का प्रशिक्षण और समीक्षा बैठक सम्पन्न

कलेक्टर एसपी सहित कई अधिकारी हुए शामिल

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पद्मिनी भोई साहू की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय सभागार में वर्ष 2023 के 3 नये कानून का प्रशिक्षण और समीक्षा बैठक सम्पन्न हुआ। कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को समन्वय के साथ 3 नये कानून का बेहतर पालन और क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसपी सुनील शर्मा, न्यायिक अधिकारी सहित जिले के कानून व्यवस्था से जुड़े राजस्व, पुलिस, चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास अधिकारी और सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे। प्रशिक्षण में जानकारी दी गई कि, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए) 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो गए हैं। आईजीओटी (आई गॉट) कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 110 ई-लर्निंग कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें से 76 कोर्स नए आपराधिक कानूनों से संबंधित हैं।न्याय संहिता में आपराधिक न्याय प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में तकनीक के इस्तेमाल का प्रावधान है। इनके लागू करने के लिए डिजिटल प्रणाली और आवेदन उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन (ई-एफआईआर), समन का इलेक्ट्रॉनिक संचार और भेजना (ई-समन), तलाशी, जब्ती और जांच की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, फोरेंसिक सबूत इकट्ठा करने की वीडियोग्राफी और बयानों की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग (ई-साक्ष्य), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (न्याय श्रुति) के जरिए अदालती कार्यवाही का संचालन, मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए एमईडीएलईएपीआर और पुलिस, अदालतों, जेलों, अभियोजन और फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के बीच एफआईआर, चार्ज-शीट और दूसरे दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान को आसान बनाने के लिए इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) शामिल है। इसका इस्तेमाल पूरे देश में किया जाता है। इन नए कानूनों का उद्देश्य जांच प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, पीड़ितों के अधिकारों को सशक्त बनाना और भारत के बढ़ते डिजिटल प्रभाव के अनुरूप न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण करना था। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) ने 1860 की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का स्थान लिया है। इसने अपराधों को सुव्यवस्थित किया है, परिभाषाओं को आधुनिक बनाया है और नए अपराधों को शामिल किया है। बीएनएसएस अंतर्गत पुलिस गंभीर अपराधों के लिए निर्धारित समय अवधि में जांच पूरी करेगी।एफआईआर, आरोप पत्र और गवाहों को समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल और तामील किए जा सकते हैं। अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना कोई भी पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कर सकता है। 7 वर्ष से अधिक की सजा वाले सभी अपराधों के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों का उपयोग अनिवार्य होगा। जमानत के हक और विचाराधीन कैदियों के अधिकारों पर अधिक स्पष्टता, पीड़ित जांच की प्रगति के बारे में अद्यतन जानकारी की मांग कर सकते हैं। गंभीर अपराधों के लिए जमानत सुनवाई में पीड़ित की भागीदारी। कुछ अपराधों में अनिवार्य मुआवजा और पुनर्वास। भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेता है और स्वीकार्यता, डिजिटल प्रलेखन और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है।

बड़ेंग वॉटरफॉल के संरक्षण एवं पर्यटन विकास हेतु ग्राम पंचायत बरूंगपाल के ग्रामीणों का ऐतिहासिक श्रमदान

जगदलपुर/मूक पत्रिका

पवन कुमार -बरूंगपाल, बस्तर। ग्राम पंचायत बरूंगपाल के लगभग 150 ग्रामीणों ने लगातार दूसरे वर्ष भी सामूहिक श्रमदान कर बड़ेंग वॉटरफॉल तक पहुँचने वाले लगभग 6 किलोमीटर मार्ग का निर्माण एवं सुधार कार्य किया। इस कार्य में ग्रामीणों ने अपने निजी ट्रैक्टर, जेसीबी एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराकर जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। इससे पूर्व वर्ष 2025 में भी ग्रामीणों ने श्रमदान के माध्यम से सड़क निर्माण एवं सुधार कार्य किया था। उस समय प्रशासन द्वारा निरीक्षण भी किया गया था, किंतु ग्रामीणों के अनुसार इसके बाद सड़क एवं पर्यटन स्थल के समुचित विकास के लिए अपेक्षित सरकारी पहल नहीं हो सकी।इस श्रमदान अभियान में जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी रही। इनमें भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य रुक्मणी कर्मा ,जनपद पंचायत सदस्य भारती कर्मा, सरपंच सोमारी, समाज सेवक पाकलू कर्मा, हिरमो वट्टी, नरेंद्र कर्मा, पांडू बेट्टी, अर्जुन कर्मा, भीमो वट्टी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।ग्रामीणों का कहना है कि पहले ग्राम पंचायतों को आवश्यक निर्माण कार्यों के लिए नियमित रूप से निधि उपलब्ध कराई जाती थी, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्य किए जाते थे। वर्तमान व्यवस्था में अधिकांश कार्य प्रस्तावों एवं स्वीकृतियों पर निर्भर हो गए हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों के आवश्यक विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि संसाधनों की कमी या अन्य कारणों से विकास कार्यों में अपेक्षित गति नहीं दिख रही है। ग्रामीणों के अनुसार इस सड़क के पूर्ण रूप से विकसित होने पर कलेपाल की दूरी लगभग 8 किलोमीटर से घटकर 3 किलोमीटर रह जाएगी। इससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा यह मार्ग एक महत्वपूर्ण शॉर्टकट के रूप में विकसित होगा।ग्रामीणों ने राज्य सरकार एवं प्रशासन से मांग की है कि बड़ेंग वॉटरफॉल को एक विकसित पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए सड़क का स्थायी निर्माण, एक लघु बाँध (डैम), पार्किंग, उद्यान (गार्डनिंग), पर्यटक सुविधा परिसर (कॉम्प्लेक्स), पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का शीघ्र निर्माण कराया जाए।

प्राथमिक शाला के पुन: संचालन पर 25 बच्चों ने लिया प्रवेश, जिले में इस सत्र 38 बंद स्कूल दोबारा खुले

21 साल बाद मेटापारा कोरसागुड़ा में गूंजी स्कूल की घंटी

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। जिले में बीते शुक्रवार को 21 साल से बंद पड़े स्कूल में एक बार फिर बच्चों की आवाज सुनाई दी। उसूर ब्लॉक के मेटापारा कोरसागुड़ा प्राथमिक शाला का लंबे अंतराल के बाद पुनः संचालन शुरू किया गया। कलेक्टर विश्वदीप की पहल से स्कूल में 25 बच्चों ने प्रवेश लिया। विद्यालय पहुंचने पर बच्चों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। स्कूल दोबारा खुलने से ग्रामीणों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल रहा। पुनः संचालन के अवसर पर बच्चों को स्लेट, पुस्तकें और पेंसिल वितरित की गईं। बच्चों के लिए यह नए शैक्षणिक सफर की शुरुआत रही। अब गांव के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होगी।

बच्चों को नियमित स्कूल आने की समझाइश–कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य शंकरैया माड़वी ने बच्चों का स्वागत किया। उन्होंने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है। बंद स्कूलों के पुनः संचालन से दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को अपने गांव में ही पढ़ाई का अवसर मिल रहा है। कार्यक्रम में सरपंच, बीईओ एमवी राव, रामकृष्ण पी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

जिले में अब तक 38 स्कूल फिर से शुरू–डीईओ राजेश पांडे ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन के प्रयासों से वर्तमान शिक्षा सत्र में जिले में अब तक 38 बंद स्कूलों का पुनः संचालन किया जा चुका है। इन स्कूलों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वैकल्पिक संसाधनों और शिक्षादूतों के माध्यम से अध्यापन शुरू कराया गया है। इससे लंबे समय से शिक्षा से दूर बच्चों को दोबारा विद्यालयों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

घोषणा अधूरी, साख बचाने विधायक के पास पहुंचे कांग्रेस समर्थित लोग!

बरमकेला /मूक पत्रिका

चौहान समाज के भवन के लिए पहले 5 लाख, फिर 10 लाख की घोषणा–राशि नहीं मिलने से आक्रोश; चुनिंदा लोगों के विधायक निवास पहुंचने पर समाज में उठे सवाल चौहान समाज के भवन निर्माण को लेकर सारंगढ़ विधायक द्वारा पहले 5 लाख और बाद में 10 लाख रुपये की घोषणा किए जाने के बावजूद राशि नहीं मिलने का मामला अब राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। घोषणा पूरी नहीं होने को लेकर चौहान समाज में पहले से ही नाराजगी है, वहीं खबर सार्वजनिक होने के बाद विधायक की साख बचाने के लिए समाज के कुछ कांग्रेस समर्थित चुनिंदा लोग विधायक निवास पहुंचकर बधाई देने पहुंचे–जिसे लेकर समाज के भीतर भारी नाराजगी बताई जा रही है। समाज के लोगों का कहना है कि जब चौहान समाज अपने भवन के लिए घोषित राशि की मांग कर रहा है और विधायक से घोषणा पूरी कराने का दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे समय में समाज की मूल मांग को मजबूती से उठाने के बजाय कुछ लोग विधायक के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इससे समाज के बीच यह सवाल उठ रहा है कि आखिर समाज का हित महत्वपूर्ण है या राजनीतिक नजदीकियां?5 लाख से 10 लाख की घोषणा, फिर भी भवन का इंतजार!चौहान समाज के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह के दौरान भवन निर्माण के लिए विधायक द्वारा राशि की घोषणा किए जाने की बात सामने आई थी। बाद में राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये किए जाने की चर्चा भी हुई। लेकिन समाज का आरोप है कि घोषणा के बावजूद आज तक भवन निर्माण के लिए अपेक्षित राशि नहीं मिली। समाज के लोगों का कहना है कि घोषणा मंच से करना आसान है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना ही असली जनप्रतिनिधित्व की कसौटी है।खबर चली तो सक्रिय हुए विधायक समर्थक? समाज के भवन की राशि को लेकर सवाल उठने और मामला सार्वजनिक होने के बाद विधायक के पक्ष में कुछ लोगों की सक्रियता चर्चा का विषय बन गई है। समाज के आक्रोशित लोगों का आरोप है कि कुछ कांग्रेस समर्थित लोग विधायक की राजनीतिक साख बचाने की कोशिश में विधायक निवास पहुंचे और बधाई दी। समाज के लोगों का कहना है कि यदि विधायक ने घोषणा की है तो समाज को बधाई की नहीं, बल्कि घोषित राशि की स्वीकृति, कार्ययोजना और निर्माण कार्य की शुरुआत की जरूरत है।

कांग्रेस समर्थित शिक्षक की भूमिका पर भी उठे सवाल–विधायक निवास पहुंचने वालों में कांग्रेस समर्थित बताए जा रहे एक शिक्षक की भूमिका को लेकर भी समाज के भीतर सवाल उठ रहे हैं। समाज का कहना है कि सामाजिक मुद्दे पर राजनीतिक पक्षधरता से ऊपर उठकर समाजहित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति समाज की मांग के विपरीत राजनीतिक समर्थन में खड़ा होता है तो समाज उसके रुख पर सवाल जरूर उठाएगा। अब सम्मान नहीं, जवाब मांगेगा चौहान समाज!चौहान समाज के लोगों का कहना है कि अब केवल घोषणा और बधाई के दौर से काम नहीं चलेगा। समाज यह जानना चाहता है कि घोषित 5 लाख और 10 लाख रुपये की राशि कहां है? स्वीकृति हुई या नहीं? कार्ययोजना बनी या नहीं? और भवन निर्माण कब शुरू होगा? समाज के भीतर इस पूरे मामले को लेकर बैठक कर निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। समाज के लोगों का कहना है कि यदि घोषणा पूरी नहीं होती और समाज की मांग को नजरअंदाज किया जाता है तो आने वाले दिनों में आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जा सकता है। चौहान समाज का संदेश साफ है–÷हमें बधाई नहीं, भवन चाहिए। हमें घोषणा नहीं, राशि चाहिए। हमें आश्वासन नहीं, काम चाहिए।÷अब सवाल सारंगढ़ विधायक से है कि घोषित राशि आखिर कब जमीन पर उतरेगी? और सवाल उन लोगों से भी है जो समाज की मांग के समय समाज के साथ खड़े होने के बजाय विधायक निवास पहुंचकर बधाई देने पहुंचे–क्या समाज की आवाज से बड़ा राजनीतिक समीकरण हो गया है?

गलत जानकारी देने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

दवा कंपनियों पर सख्तीः केंद्र ने ड्रग्स नियमों में किए बदलाव

दवा रेगुलेटरी व्यवस्था की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को मजबूत करना मकसद

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 'ड्रग्स रूल्स, 1945' में संशोधन किया है। इसके तहत लाइसेंस देने वाले अधिकारियों को उन आवेदकों को प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया गया है, जो रेगुलेटरी मंजूरी के लिए आवेदन करते समय नकली या मनगढ़ंत डेटा जमा करते हैं। इस कदम का मकसद भारत की दवा रेगुलेटरी व्यवस्था की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को मजबूत करना है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जीएस आर 756(ई) के माध्यम से अधिसूचित संशोधनों में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत मौजूदा प्रावधानों के अतिरिक्त एक नया प्रवर्तन तंत्र पेश किया गया है। संशोधित नियमों के तहत, अगर किसी आवेदक ने गलत या बनावटी डेटा जमा किया है, तो उसे संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी (चाहे वह केंद्र हो या राज्य का रेगुलेटर, जो भी लागू हो) के पास एक तय समय के लिए नए आवेदन करने से रोका जा सकता है।

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत पहले से मौजूद लागू करने वाले प्रावधानों के अलावा, हाल ही में नोटिफाई किए गए ये प्रावधान लाइसेंसिंग अथॉरिटी को यह अधिकार देते हैं कि वे उन संस्थाओं के आगे के आवेदनों पर रोक लगा सकें जो अपने आवेदनों के समर्थन में नकली या मनगढ़ंत डेटा जमा करती हैं।' मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'यह नियम औषधि नियम 1945 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दायर सभी आवेदनों पर लागू होगा।' वर्तमान में, मनगढ़ंत डेटा प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को आवेदन अस्वीकृत करने या मौजूदा लाइसेंस रद्द करने जैसी प्रवर्तनीय कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है।

अभी, जो आवेदक गलत या बनावटी जानकारी देते हैं, उनके आवेदन खारिज किए जा सकते हैं या उनके मौजूदा लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। इस बदलाव के बाद, उन्हें एक तय समय के लिए संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी (राज्य या केंद्र, जो भी लागू हो) के पास और आवेदन जमा करने से रोक दिया जाएगा।

इसमें कहा गया है कि नकली या मनगढ़ंत डेटा जमा करने से रेगुलेटरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है, दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं और इससे जन-स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो सकते हैं। इस संशोधन का मकसद ऐसी गलत हरकतों को रोकना, आवेदकों की जवाबदेही बढ़ाना है। यह पक्का करना है कि दवाओं को मंजरी भरोसेमंद और वैज्ञानिक रूप से सही सबूतों के आधार पर मिले।

यह नोटिफिकेशन, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से भारत के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत करने की सरकार की कोशिशों के अनुरूप है।उन दवा बनाने वालों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बढ़ावा देना है जो रेगुलेटरी नियमों का पालन करते हैं।

इसके साथ ही गलत कामों के सामने आए मामलों से निपटना भी है। यह फार्मा सेक्टर में चल रहे रेगुलेटरी सुधारों को और मजबूत करता है, जिसमें निगरानी बढ़ाने, नैतिक तौर-तरीकों को बढ़ावा देने और गलत काम करने वालों को उचित सजा देने पर नए सिरे से जोर दिया गया है।

560 करोड़ बैंक फ्रॉड में आईएएस अफसर की बेल रिजेक्ट

» बचाव पक्ष बोला- न रिश्वत ली, न कोई मनी ट्रेल मिला, कोर्ट ने सीबीआई का तर्क मजबूत माना

पंचकूला। पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 560 करोड़ रुपए से अधिक के सरकारी फंड घोटाले में आईएएस अफसर पंकज अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सीबीआई ने 22 जून को अग्रवाल को अरेस्ट किया था। गुरुवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।

अग्रवाल की ओर से वकीलों ने दलील दी कि केस की मूल एफआईआर में उनका नाम नहीं था। न तो कोई रिश्वत मांगी या स्वीकार की। न ही जांच में उनके खिलाफ किसी तरह की मनी ट्रेल या अवैध संपत्ति की बरामदगी हुई है। दूसरी तरफ सीबीआई ने बेल एप्लीकेशन के विरोध में तर्क दिया कि अग्रवाल के इस फ्रॉड के मास्टर माइंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्व अधिकारी रिभव ऋषि के करीबी संपर्क थे। इसके बदले अफसर को आर्थिक और अन्य अनुचित लाभ मिले। सरकारी पैसा इधर से उधर करने में सक्रिय भूमिका रही। उल्लेखनीय है कि पंकज अग्रवाल 10 दिसंबर 2024 से 16 जून 2025 तक स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव रहे। इसी दौरान हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद का खाता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खुलवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। फिर 31 दिसंबर 2024 को कोटक महिंद्रा बैंक से 100 करोड़ रुपये इस खाते में ट्रांसफर करने की मंजूरी दी।

बचाव पक्षः सभी सबूत पुलिस के पास, जेल में रखने का औचित्य नहीं- पंकज अग्रवाल 22 जून 2026 से हिरासत में हैं और उनकी जमानत अर्जी में बचाव पक्ष ने मुख्य तर्क दिया है कि जांच एजेंसी के पास मामले से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक व दस्तावेजी साक्ष्य पहले से मौजूद हैं, इसलिए अब उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। 100 करोड़ रुपए के ट्रांसफर को लेकर सफाई देते हुए वकील ने कहा कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद का पैसा किसी गैर-कानूनी या अप्रमाणित बैंक में नहीं भेजा गया था। यह राशि पहले से ही सरकार द्वारा सूचीबद्ध कोटक महिंद्रा बैंक में जमा थी, जिसे नियमानुसार दूसरे सूचीबद्ध IDFC फर्स्ट बैंक में ट्रांसफर किया गया।

स्कूल के गेट का आर्च गिरने से छात्र की मौत

» चौकीदार के बेल खींचते ही भरभराकर गिरा; सोनीपत में टीचर्स ने टेबल पकड़ने को कहा था

सोनीपत। सोनीपत में छठीं क्लास के बच्चे के ऊपर सरकारी स्कूल के गेट का आर्च गिर गया। मलबे में दबने से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में आसपास के लोगों और टीचर्स ने उसे खानपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।

कुछ ही देर बाद इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। घटना गन्नौर के गढ़ी बिलंदा के राजकीय स्कूल में हुई। यहां स्कूल का चौकीदार टेबल पर खड़ा होकर आर्च पर लगी बेल हटा रहा था। बेल हटते ही अचानक आर्च निचे गिर गया। आर्च की ईंटें नीचे टेबल पकड़कर खड़े यश (11) के ऊपर गिर गई। यश बेगा के राजकीय स्कूल में पढ़ता था। आज बारिश के कारण स्कूल नहीं गया था।

परिजनों का कहना है कि गेट का आर्च घटिया सामग्री से बनाया गया था और दो कमरे भी खस्ताहाल हैं। बरामदे का लेंटर झड़ रहा है, दीवार में दरारें पड़ी हैं। इसके बाद भी मरम्मत कराने के बजाय पेंट कर दिया गया, ताकि साफ-सुथरा दिखाई दें। गन्नौर में गढ़ी बिलंदा राजकीय प्राथमिक स्कूल में बारिश के मौसम में स्कूल का चौकीदार उदय साफ- सफाई कर रहा था। स्कूल के मेन गेट पर बने आर्च पर एक बेल भी लगी थी। उदर बेल को हटाने के लिए ऊपर चढ़ गया। जैसे ही उसने बेल पकड़कर खींची, इसी दौरान आर्च धड़ाम से नीचे गिर गया। रास्ते से छठीं क्लास का छात्र यश गुजर रहा था। आर्च का मलबा यश के ऊपर गिर गया। यश के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्कूल में पढ़ा रहे टीचर्स तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे और उसे मलबे से बाहर निकाला। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना गन्नौर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। आसपास मौजूद लोगों और स्कूल स्टाफ से भी जानकारी जुटाई गई है।

विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति

» पीएम मोदी ने नेतन्याहू से फोन पर की बात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच गुरुवार को टेलीफोन पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और भारत-इस्राइल के विशेष रणनीतिक संबंधों की समीक्षा की। बातचीत में दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, दोनों नेताओं ने भविष्य में भी नियमित संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि बातचीत के दौरान भारत और इस्राइल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देश आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिति को लेकर अपने-अपने विचार साझा किए। हाल के समय में पश्चिम एशिया में बदलते घटनाक्रमों के बीच यह बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, बातचीत के संबंध में किसी विशेष मुद्दे या निर्णय का अलग से उल्लेख नहीं किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने भारत-इस्राइल विशेष रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने रक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि, नवाचार, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों का मानना है कि इन क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग दोनों देशों के साझा हितों और विकास के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।

बातचीत के अंत में प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने भविष्य में भी संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि दोनों नेता आपसी हितों और क्षेत्रीय मुद्दों पर लगातार संवाद जारी रखेंगे। भारत और इस्राइल के बीच वर्षों से विकसित रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने सहयोग को नई गति देने की इच्छा जताई।

चेतावनी लेबल का असरः घटी हानिकारक खाद्य पदार्थों की बिक्री

नई दिल्ली। आकर्षक पैकेजिंग और बड़े-बड़े स्वास्थ्य संबंधी दावों के बीच उपभोक्ताओं के लिए सही खाद्य पदार्थ चुनना चुनौती बनता जा रहा है। लैटिन अमेरिका के कई देशों में अधिक चीनी, नमक और संतृप्त वसा वाले खाद्य पदार्थों पर चेतावनी चिह्न लगाने की व्यवस्था पहले से लागू है। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि ऐसे लेबल लागू होने के बाद इन उत्पादों की बिक्री में उल्लेखनीय कमी आई है। हालांकि, इन उपायों का लोगों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव जानने के लिए शोध अभी जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी पैकेज्ड खाद्य उत्पाद की वास्तविक गुणवत्ता का आकलन उसके विज्ञापन या पैकेट पर लिखे दावों से नहीं, बल्कि पोषण संबंधी जानकारी और सामग्री की सूची से किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार, कई उत्पाद स्वयं को स्वास्थ्यवर्धक बताकर बाजार में उतारे जाते हैं, जबकि उनमें अतिरिक्त चीनी, सोडियम और संतृप्त वसा की मात्रा अधिक होती है। ऐसे में खरीदारी से पहले पोषण संबंधी विवरण पढ़ना और उत्पाद की वास्तविक संरचना समझना जरूरी है। उपभोक्ताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ऐसा प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसके तहत पैकेज के सामने ही संतृप्त वसा, अतिरिक्त चीनी और सोडियम की मात्रा को कम, मध्यम या अधिक श्रेणी में दर्शाया जाएगा। इससे उपभोक्ता बिना पूरी जानकारी पढ़े भी उत्पाद की पोषण गुणवत्ता का आसानी से आकलन कर सकेंगे।

धोखाधड़ी से बैंक लोन लिया, फिर पैसे को दूसरी जगह लगाया

ईडी ने जब्त की 150 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत लगभग 51.28 करोड़ रुपये (बाजार मूल्य लगभग 150 करोड़ रुपये या उससे अधिक) की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। यह कार्रवाई दीपक केबल (इंडिया) लिमिटेड (डीसीआईएल), इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के. वेंकटेश्वर राव, डायरेक्टर सत्यवती बॉल और उनसे जुड़ी कंपनियों द्वारा बैंक धोखाधड़ी, लोन के पैसे को दूसरी जगह लगाने और हड़पने से जुड़े मामले में की गई है।

ईडी ने सीबीआई, बीएसएंडएफबी, बेंगलुरु द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। इसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल, शामिल है। इन सबके चलते कंसोर्टियम बैंकों को गलत तरीके से भारी नुकसान हुआ है। जांच से पता चला कि डीसीआईएल और इसके प्रमोटरों ने हेरफेर किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया। इसके बाद स्टॉक स्टेटमेंट और गलत देनदार (डेटर) स्टेटमेंट जमा करके कंसोर्टियम बैंकों के साथ धोखाधड़ी कर कई क्रेडिट सुविधाएं हासिल कीं। उनका अनुचित लाभ उठाया। जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने सामान की वास्तविक आवाजाही के बिना ही नकली खरीद-बिक्री के लेन-देन करके, संबंधित कंपनियों के एक नेटवर्क के जरिए बैंक लोन के पैसे को दूसरी जगह लगाया और हड़प लिया। इन संबंधित कंपनियों में सूर्य ट्रांसमिशन लिमिटेड, आधुनिक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, दंडदेली फेरो प्राइवेट लिमिटेड, शरावती कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, वेंकटेश इंडस्ट्रीज, मारुति इंजीनियरिंग वर्क्स, यूनिवर्सल ट्रांसमिशन लाइन प्रोडक्ट्स, केजीएन इलेक्ट्रिकल्स और अन्य जुड़ी हुई कंपनियां शामिल हैं। लोन से मिली रकम को उन कामों में लगाया गया, जिनके लिए लोन मंजूर नहीं हुआ था। इनमें जुड़ी हुई कंपनियों के जरिए प्राइवेट इक्विटी निवेशकों से इक्विटी शेयर वापस खरीदना और एसेट खरीदना शामिल है।

थाने के सामने 7 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग

30 गोलियां मारीं, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी; 3 हमलावर रिवॉल्वर लहराते भागे

भिवानी। हरियाणा के दादरी शहर में सिटी थाने के सामने गुरुवार को अंधाधुंध फायरिंग हुई। इस दौरान ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार 7 लोगों को गोलियां मारी गईं। सभी को सिविल अस्पताल लाने के बाद रोहतक रेफर कर दिया गया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सिटी थाने के ठीक सामने 3 बदमाश बाइक पर बैठकर आए और गाड़ी रुकवाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 30 राउंड फायरिंग से ब्लैक स्कॉर्पियो को छलनी किया। गोलियों की गूंज से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार कोर्ट से पेशी भुगतकर आ रहे थे। पुलिस इसे गैंगवार मान रही है। बताया जा रहा है, इन सात लोगों पर विभिन्न मामलों में 43 मुकदमे दर्ज हैं। घटना के 2 वीडियो भी सामने आए। एक में ब्लैक स्कॉर्पियों में लहूलुहान युवक बैठे दिख रहे हैं। वहीं, दूसरे में तीन हमलावर हाथ में रिवॉल्वर लेकर भागते दिखे। तीनों भरे बाजार में हथियार लहराते और गालियां देते जा रहे थे।

घटना के बाद रोहित गोदारा गैंग की एक ऑडियो सामने आई है, हालांकि दैनिक भास्कर इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। ऑडियो में गैंग मेंबर नवीन बॉक्सर ने कहा- राम-राम सारे भाइयों नै...मैं नवीन बॉक्सर, रोहित गोदारा ग्रुप से। आज दादरी के अंदर अमित फतेहगड़िया के ऊपर अटैक हुआ है, इसके 2 साथी मरे हैं। इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। सभी कान खोलकर सुन लेना, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। इनके साथ चलने वाला हमारा दुश्मन होगा।

बाइक पर आए बदमाश, स्कॉर्पियो रुकवाकर बरसाईं गोलियां- पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि तीन बदमाश एक बाइक पर सवार होकर आए। आरोपियों ने थाने के सामने स्कॉर्पियो के आगे बाइक अड़ाकर उसे रुकवा लिया। इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों हमलावर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। एक हमलावर की फुटेज भी सामने आई। फायरिंग में 7 लोगों के घायल होने की सूचना है। इनमें अंकित (चरखी दादरी), कीर्तिमान (हिसार), सूरज (मानहेरू), अंकित (भिवानी), सनी (हिसार), कृष्ण (महेंद्रगढ़) और अमित (फतेहगढ़) शामिल हैं। सभी को पहले दादरी सिविल अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद उन्हें रोहतक के कायनोस अस्पताल में भर्ती कराया गया।

एसपी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे- घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक, डीएसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। मौके से बरामद गोलियों के खोल और अन्य सुरागों की भी जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान हो सके। इसके साथ ही आसपास के थाना क्षेत्रों को भी अलर्ट कर दिया गया है और संदिग्ध वाहनों व बदमाशों की तलाश में नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

दुनिया को टैरिफ का डर दिखाते-दिखाते खुद फंसे ट्रंप, अमेरिका लौटा रहा 100 अरब डॉलर

वाशिंगटन। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) की ओर से दायर एक याचिका के अनुसार अमेरिका ने ट्रंप के 'लिबरेशन डे' टैरिफ के तहत लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर का रिफंड प्रोसेस किया है। इन टैरिफ को बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। यह एजेंसी के इतिहास में टैरिफ रिफंड की सबसे बड़ी कोशिशों में से एक है। यह रिफंड अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम के तहत लगाए गए अतिरिक्त मूल्य-आधारित शुल्कों से संबंधित है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में रद्द कर दिया था। संसाधित राशि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित टैरिफ के तौर पर जमा किए गए लगभग 166 अरब अमेरिकी डॉलर के आधे से ज्यादा हिस्से के बराबर है।

सीबीपी के व्यापार कार्यालय में व्यापार कार्यक्रम निदेशालय के कार्यकारी निदेशक ब्रेंडन लॉर्ड की ओर से दायर घोषणा के अनुसार, एजेंसी ने अपने ऑटोमेटेड कमर्शियल एनवायरनमेंट प्लेटफॉर्म में योग्य रिफंड की गणना और प्रोसेसिंग के लिए एक नई सिस्टम क्षमता विकसित की है। वहीं, कंसोलिडेटेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एंट्रीज' नाम की नई सुविधा 20 अप्रैल, 2026 को इंपोर्टर्स और कस्टम्स ब्रोकर्स के लिए उपलब्ध हो गई। लॉर्ड ने अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में दायर घोषणा में कहा,' शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को ईस्टर्न टाइम के अनुसार दोपहर 3 बजे तक, CAPE में प्रोसेसिंग के लिए लगभग 128.68 अरब अमेरिकी डॉलर के संभावित और सर्टिफाइड रिफंड स्वीकार किए जा चुके हैं।' उन्होंने आगे कहा कि सीएपीई रिफंड घटक के माध्यम से शुल्क और ब्याज सहित लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि का रिफंड पूरा हो चुका है, जिसे सीबीपी की ओर से प्रमाणित किया गया है और वितरण के लिए अमेरिकी वित्त विभाग को भेज दिया गया है। सीबीपी ने बताया कि सीएपीई प्रणाली ने शुरू होने के बाद से लाखों धनवापसी आवेदनों पर कार्रवाई की है। 31 जुलाई, 2026 तक, 252,496 सीएपीई आवेदन जमा किए गए थे, जिनमें से 178,213 आवेदन सत्यापन में सफल रहे।

जिला जेल बेमेतरा में 28 बंदियों को दिया गया दो दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण

कौशल विकास एवं स्वरोजगार की दिशा में सार्थक पहल

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कृषि विज्ञान केंद्र, बेमेतरा द्वारा जिला जेल बेमेतरा में बंदियों के कौशल विकास, स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 6 एवं 7 अगस्त 2026 को दो दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला जेल बेमेतरा के 28 बंदियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र, बेमेतरा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख तोषण ठाकुर के मार्गदर्शन में किया गया। प्रशिक्षण का संचालन कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक डॉ. राजनी डी. अगाशे एवं डोमन सिंह टेकाम द्वारा किया गया।दो दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को मशरूम उत्पादन की आधुनिक एवं व्यावहारिक तकनीकों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में मशरूम उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री, सब्सट्रेट तैयार करने की विधि, स्पॉन की जानकारी, उत्पादन की विभिन्न अवस्थाएं, स्वच्छता एवं आवश्यक सावधानियां, उचित तापमान एवं नमी का प्रबंधन, फसल की देखभाल एवं तुड़ाई सहित मशरूम के विपणन एवं मूल्य संवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को व्यावहारिक प्रदर्शन के माध्यम से मशरूम उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से समझाया गया। इससे बंदियों को मशरूम उत्पादन की तकनीक को केवल सैद्धांतिक रूप से समझने के साथ-साथ इसे व्यवहार में अपनाने की जानकारी भी प्राप्त हुई। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि मशरूम उत्पादन कम स्थान, कम लागत और सीमित संसाधनों में स्वरोजगार का बेहतर माध्यम बन सकता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बंदियों को ऐसा उपयोगी एवं रोजगारपरक कौशल प्रदान करना है, जिसे वे जेल से बाहर आने के बाद भी अपनाकर अपनी आजीविका का साधन बना सकें और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकें।कार्यक्रम के सफल आयोजन में कृषि विज्ञान केंद्र, बेमेतरा के कमलेश बघेल, मिलाप वर्मा एवं अन्य कर्मचारियों का सराहनीय सहयोग रहा। वहीं, जिला जेल बेमेतरा के अधीक्षक राहुल पाण्डेय तथा जेल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के सुचारु संचालन में महत्वपूर्ण सहयोग एवं समन्वय प्रदान किया। दो दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान सभी 28 प्रतिभागियों ने सक्रिय एवं उत्साहपूर्ण सहभागिता निभाई। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों के कौशल विकास, स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सार्थक पहल के रूप में सामने आया।

बारिश में खुली सरकारी व्यवस्था की पोल, दफ्तरों में बाल्टी, कॉलोनियों में तिरपाल कर्मचारी पूछ रहे, 'छत कब मिलेगी

रायगढ़/मूक पत्रिका

जिला राजस्व कमाने में प्रदेश के प्रमुख जिलों में शामिल है। खनिज संपदा से लेकर उद्योगों तक, सरकारी खजाने में करोड़ों की राशि पहुंचती है। लेकिन इसी समृद्ध जिले के घरघोड़ा में शासन के अपने ही कार्यालय और कर्मचारी कॉलोनियां ऐसी हालत में हैं कि बारिश आते ही सरकारी व्यवस्था की छत से पानी टपकने लगता है। यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं, बल्कि घरघोड़ा के कई शासकीय भवनों और कर्मचारी आवासों की जमीनी हकीकत है। तहसील कार्यालय, कृषि विभाग, आरईएस, जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और वन विभाग जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों में भवनों की जर्जर स्थिति कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। बारिश के दिनों में कई जगह छत से पानी टपकने की शिकायत सामने आती है। जिन सरकारी कार्यालयों में जनता की समस्याओं और विकास योजनाओं की फाइलें तैयार होती हैं, वहां बारिश के दौरानकर्मचारियों की प्राथमिकता बदल जाती है कहीं बाल्टी रखी जाती है, कहीं पानी से दस्तावेज बचाने की कवायद होती है और कहीं छत पर तिरपाल का सहारा लिया जाता है। व्यंग्यात्मक सवाल यह है कि क्या अब सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए 'बारिश से बचाव मिशन' शुरू करना पड़ेगा? शिक्षक कॉलोनी, वन विभाग कॉलोनी, पुलिस विभाग कॉलोनी, जल संसाधन विभाग कॉलोनी और कर्मचारी कॉलोनी में भी जर्जर आवासों को लेकर कर्मचारियों और उनके परिवारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बारिश में छत से पानी टपकना, दीवारों में सीलन और भवनों की खराब हालत के बीच कई परिवार छत पर तिरपाल डालकर रहने को मजबूर हैं।

दर्रामुड़ा में स्ट्रीट लाइटें बंद, अंधेरे से ग्रामीण परेशान

खरसिया/मूक पत्रिका

जनपद पंचायत खरसिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत दर्रामुड़ा में सरपंच द्वारा लगाई गई कई स्ट्रीट लाइटें खराब होने के कारण लंबे समय से बंद पड़ी हैं। गांव के अनेक बिजली खंभों पर स्ट्रीट लाइट नहीं जलने से रात होते ही कई मोहल्लों में अंधेरा छा जाता है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अंधेरे के कारण रात के समय दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष रूप से परेशानी उठानी पड़ रही है। साथ ही असामाजिक तत्वों की गतिविधियों और जहरीले जीव-जंतुओं का भी खतरा बना रहता है।ग्रामीणों ने बताया कि कई स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब हैं, लेकिन अब तक उनकी मरम्मत नहीं कराई गई है। इससे पंचायत की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत एवं संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि गांव की सभी खराब स्ट्रीट लाइटों की शीघ्र मरम्मत कर उन्हें चालू कराया जाए, ताकि लोगों को अंधेरे से राहत मिल सके और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित हो सके।

जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक सम्पन्न, आगामी पर्व-त्योहारों को लेकर हुए महत्वपूर्ण चर्चा

जिले में आगामी पर्व-त्योहारों को शांति, सौहार्द्र एवं आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण मनाने हेतु की गई अपील

बेमेतरा/मूक पत्रिका

आगामी पर्व-त्योहारों के मद्देनजर जिला मुख्यालय बेमेतरा के पुराना रेस्ट हाऊस में बीते शनिवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं एवं पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव, अपर कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज एवं एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का, तहसीलदार अनिरूद्ध मिश्रा, रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो, थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा प्रभारी निरीक्षक सोनल ग्वाला, जनप्रतिनिधियों, समाज प्रमुखों, विभिन्न विभागों के अधिकारी, सहित जिले के गणमान्य नागरिक एवं प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण की उपस्थिति में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में आगामी हरेली, ईद-ए-मिलाद (मिलाद-ऊन- नबी), रक्षा बंधन, कांवर यात्रा, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दुर्गा उत्सव, दशहरा एवं दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जिले में सामाजिक सौहार्द्र, आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने संबंधी विषयों पर गहन चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए एएसपी डॉ. हरीश यादव ने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहेगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर स्तर पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी पर्व-त्योहारों में डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा अत्यधिक तेज़ आवाज़ में साउंड सिस्टम बजाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों से दूर रहें और किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत पुलिस अथवा प्रशासन से संपर्क करें। अपर कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज ने कहा कि बेमेतरा जिला हमेशा से सामाजिक समरसता और भाईचारे की मिसाल रहा है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि आगामी त्योहार शांति, अनुशासन और आपसी सहयोग के साथ सम्पन्न हों। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि पर्व-त्योहारों के दौरान पेयजल आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएँ और स्वच्छता की स्थिति पूरी तरह दुरुस्त रखी जाए, ताकि श्रद्धालुओं और नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक में यह जानकारी दी गई कि आगामी पर्व-त्योहारों में पंडाल सड़कों पर न बनाए जाएं, जिससे आवागमन बाधित न हो और आमजन को परेशानी न हो। केवल मिट्टी से बनी प्रतिमाओं की स्थापना की अनुमति होगी। पंडालों की सुरक्षा की जवाबदारी आयोजकों की होगी तथा सभी पूजा पंडालों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य रहेगा। आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान गरबा एवं आर्केस्ट्रा के आयोजन के लिए एसडीएम से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की सूची संबंधित थाना में उपलब्ध कराना भी अनिवार्य रहेगा।

नकली सोने का हार असली बताकर ग्रामीण से 10 हजार की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार, थाना नगरनार जिला जगदलपुर पवन कुमार नाग

जगदलपुर/मूक पत्रिका

नगरनार क्षेत्र में नकली सोने के हार को असली बताकर ग्रामीण से 10 हजार रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से ठगी की रकम समेत नकली सोने की तीन मालाएं और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार, मंगनपुर निवासी लिगेश्वर सेठिया ने थाना नगरनार में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 6 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे वह काम से जगदलपुर जाने के लिए घर से निकल रहा था। इसी दौरान दो व्यक्ति उसके घर पहुंचे। इनमें से एक ने अपना नाम मोहन लाल सोलंकी निवासी भिलाई-दुर्ग बताया और पैसों की जरूरत बताते हुए करीब पांच लाख रुपये कीमत का सोने का हार होने की बात कही।आरोपी ने हार दिखाकर ग्रामीण से 10 हजार रुपये तत्काल देने की मांग की और शेष राशि अगले दिन देने की बात कही। ग्रामीण ने 10 हजार रुपये देकर हार अपने पास रख लिया। बाद में जब उसने हार को सोनार की दुकान पर जांच कराया तो वह असली सोना नहीं, बल्कि पीतल मिश्रित नकली हार निकला। इसके बाद पीड़ित ने नगरनार थाने में शिकायत दर्ज कराई।रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 117/2026, धारा 318(4), 35 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने तलाश के बाद मोहन लाल सोलंकी (52) निवासी नेहरू चौक, चरौदा, थाना भिलाई-3, जिला दुर्ग और मोहन राय (52) निवासी हथनीपारा वार्ड, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार को गिरफ्तार किया।पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपराध करना स्वीकार किए जाने की बात पुलिस ने कही है। आरोपियों के कब्जे से 4,950 रुपये नकद, तीन नग नकली सोने की माला (कुल वजन 342.190 ग्राम) और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर के दिशा-निर्देशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक सुमीत कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक विकेश तिवारी के नेतृत्व में की गई।

गंभीर अग्नि एवं सुरक्षा खतरों के मद्देनजर, ओला इलेक्ट्रिक सर्विस सेंटर सील, 280 इलेक्ट्रिक वाहन एवं लिथियम-आयन बैटरियों का मिला भंडारण, फायर सेफ्टी के इंतजाम भी नहीं थे

रायगढ़/मूक पत्रिका

काशीराम चौक स्थित ओला इलेक्ट्रिक सर्विस सेंटर में इलेक्ट्रिक वाहनों एवं लिथियम-आयन बैटरियों के असुरक्षित भंडारण की शिकायत पर जिला प्रशासन ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए सर्विस सेंटर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य वाणिज्यिक क्षेत्र में संभावित अग्नि दुर्घटना से जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

कार्यपालिक दंडाधिकारी एवं तहसीलदार रायगढ़ श्री शिव कुमार डनसेना तथा नायब तहसीलदार पुसौर श्री प्रतीक देवांगन के जांच दल ने 07 अगस्त को मौके पर पहुंचकर परिसर का सघन निरीक्षण किया। जांच के दौरान करीब 280 इलेक्ट्रिक वाहन एवं हाई-वोल्टेज लिथियम-आयन बैटरियों का असुरक्षित एवं अव्यवस्थित तरीके से भंडारण पाया गया। वाहनों और बैटरियों को बिना पर्याप्त वेंटिलेशन वाले टिन शेड में रखा गया था, जबकि कई वाहन परिसर के बाहर भी खड़े पाए गए।

निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गंभीर कमियां सामने आईं। परिसर में आग बुझाने के लिए आवश्यक अग्निशामक यंत्र, सीओ-2 अथवा क्लास-डी अग्निशामक व्यवस्था, रेत की बाल्टियां अथवा अन्य प्रभावी अग्नि नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध नहीं पाई गई। इलेक्ट्रिक वाहनों और हाई-वोल्टेज लिथियम-आयन बैटरियों के इस प्रकार असुरक्षित भंडारण को देखते हुए परिसर में आग लगने की स्थिति में गंभीर जनहानि और संपत्ति के नुकसान की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की। जांच दल द्वारा मौके पर आधिकारिक पंचनामा तैयार किया गया। तकनीशियन चंद्र प्रकाश आदित्य की उपस्थिति में प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से सील किया गया। कार्रवाई में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर आम नागरिकों के जीवन को जोखिम में डालने वाली गतिविधियों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

जिला कोंडागांव में कल्चर के 100त्न निःशुल्क वितरण पर उप संचालक कृषि ने दिया आश्वासन

छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ जिला-कोंडगांव ने उप संचालक कृषि कैलाश नाथ मरकाम को सौंपा ज्ञापन

कोंडागांव/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ, जिला कोंडागांव के अध्यक्ष संतू राम सोरी के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारियों ने आज उप संचालक कृषि, जिला कोंडागांव कैलाश नाथ मरकाम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संघ ने मांग की कि जिले के समस्त 05 विकासखण्डों में किसानों के वितरण हेतु भण्डारित कल्चर को किसी भी शासकीय योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत अनुदान पर समायोजित कर कृषकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। संघ ने अवगत कराया कि वर्तमान में कल्चर का विक्रय नगद अथवा 50 प्रतिशत अनुदान पर किया जा रहा है। इससे मैदानी स्तर पर कार्यरत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों पर वसूली एवं आर्थिक जवाबदेही का अत्यधिक दबाव बन रहा है। लक्ष्य के अनुरूप उठाव नहीं होने से भण्डारित सामग्री के खराब होने एवं शासकीय राशि अवरुद्ध होने की संभावना बनी हुई है, जिससे मैदानी अमले का मुख्य कार्य विस्तार एवं तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में उप संचालक कृषि श्री कैलाश नाथ मरकाम जी ने मैदानी अधिकारियों की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि आदान सामग्री कल्चर को शत-प्रतिशत निःशुल्क वितरण करवाने के लिए समायोजित किया जाएगा। संघ ने इस सकारात्मक पहल के लिए उप संचालक कृषि का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे कल्चर का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित होगा तथा मैदानी अधिकारियों को राहत मिलेगी।

ज्ञापन सौंपने के दौरान उपस्थित पदाधिकारीः सूर्य कांत नागेश - संरक्षक, लकेश सेठिया - उपाध्यक्ष, तरुण विकास सोनवानी - सचिव, खोमेश्वर साहू - सहसचिव, विश्वनाथ मरकाम - संगठन मंत्री, दिनेश कुमार नाग - सहलाकर, आलोक यादव - प्रवक्ता, मनोज नेताम - सदस्य, सुमन साहू - सदस्य, सुमंत साहू - सदस्य, नवल मरकाम - ब्लॉक अध्यक्ष केशकाल, गुलशन गावड़े सदस्य , एम आर नेताम,मेघनाथ साहू ब्लाक अध्यक्ष फरसगांव,आशिष नेताम मंगल नेताम सदस्य गजेन्द्र पांडे, सदस्य,श्रीमती सरस्वती धर - सदस्य एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। जारीकर्ताः संतू राम सोरी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ जिला - कोंडागांव (छ.ग.) मोबाइलः 9691970508

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।